राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 253 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,11 मार्च 2021, मूल्य रु. 1.50

संक्षिप्त समाचार

आयोग ने बंगाल के डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया

नई दिल्ली, (संवाददाता)। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देकर उनके स्थान पर पी नीरजनयन की नियुक्ति की। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को दिए निर्देश में कहा कि वीरेंद्र को ऐसा कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावों से जुड़ा हो। राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद फैसला किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के आदेश का अनुपालन तत्काल किया जाए।

मुसीबत में पाक को भारत का ही सहारा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बदतर समय में भारत ने कई देशों को अपने यहां बनी वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है और अब भी पहुंचा रहा है। इस कड़ी में अब पाकिस्तान को भी ये वैक्सीन मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सरकार की ओर से भी इस बारे में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत द्विपक्षीय आधार पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षा गठबंधन के आधार पर पाकिस्तान को 4 करोड़, 50 लाख वैक्सीन डोज मुहैया कराएगा। अंतरराष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षा गठबंधन वैक्सीन से जुड़ा एक गठबंधन है, जिसने दुनियाभर के करीब आधे बच्चों को दुर्बल और खतरनाक संक्रामक रोगों से बचाने के लिए वैक्सीनेट किया है।

चंबा सड़क दुर्घटना में 7 की मौत, 10 घायल

चंबा, (एजेंसी)। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। निजी बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बुधवार को हुआ है। पुलिस ने आठ शव बरामद कर लिए हैं। वहीं, बताया जा रहा है कि 10 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार, चम्बा के तीसा में कॉलोनी मोड़ के पास दर्दनाक बस हादसा हुआ है। निजी बस में 20-25 लोग सवार थे।

तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

देहरादून, (एजेंसी)। उत्तराखंड में पिछले चार दिनों से जारी राजनीतिक गहमागहमी के बाद बुधवार को बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के 10वें मुख्यमंत्री बन गए। शाम 4 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। इससे पहले विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने तीरथ सिंह रावत को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। शपथ ग्रहण समारोह में सरकार के मंत्री समेत अनेक बड़े नेता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पद का शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा- मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। मैंने आरएसएस में सबको साथ लेकर चलने की ट्रेनिंग पाई है। मैंने पूर्व पीएम अटल जी के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अटल जी ने हमारे साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। ट्रेन में तीसरी श्रेणी में यात्रा की इससे मुझे प्रेरणा मिली। मेरी सफलता में संघ से प्रेरणा मिली। पत्नी, माता पिता सबका हाथ है।

इससे पहले विधायक दल का नेता चुने जाने के तीरथ सिंह रावत ने कहा था, आप लोगों के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा हूं। मैं छोटे से गांव से आया हूं। कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री बनूंगा। आज भी कह सकता हूं कि जो बड़ों ने दायित्व दिया वो मैंने निभाया। आज भी जो जिम्मेदारी दी गई है आपके सहयोग से उसे भी निभाऊंगा। प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करूंगा, टीम भावना से आगे बढ़ेंगे। त्रिवेंद जी ने जो प्रदेश का विकास किया है पिछले 10 साल में ऐसा काम नहीं हुआ। हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तीरथ सिंह का जन्म 9 अप्रैल 1964 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वर्तमान में वह पौड़ी लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। इससे पहले साल 2012-2017 में चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वह बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रैजुएट और पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह आरएसएस के साथ बतौर सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने छोड़ी पार्टी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने बुधवार को पार्टी से अपने इस्तीफे की खुद घोषणा की। चाको ने अपना इस्तीफा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। केरल विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पीसी चाको के इस्तीफे को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। चाको ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा समूहवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केरल में पार्टी बहुत सक्रिय है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी केरल में दो अलग पार्टियों की तरह काम कर रही है। चाको केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से संसद के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना पतवार की नाव बनकर रह गई है जिसे एक साल से अधिक समय से कोई अध्यक्ष नहीं मिला।

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पीसी चाको ने कहा कि मैं पिछले कई दिनों से इस फैसले पर विचार-विमर्श कर रहा था। उन्होंने कहा कि केरल कांग्रेस की टीम के साथ काम करना मुश्किल है। मैं केरल से आता हूं, जहां कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। यहां सिर्फ दो पार्टियां हैं- कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (ए) जो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दो समूहों के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केरल एक महत्वपूर्ण चुनाव का सामना करने जा रहा है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा समूहवाद फैलाया जा रहा है। मैंने आलाकमान से इसे समाप्त करने की अपील भी की, लेकिन हाईकमान दोनों समूहों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सहमत है। पीसी चाको ने आरोप लगाया कि 6 अप्रैल को होने वाले केरल चुनाव के लिए कांग्रेस में अलोकतांत्रिक तरीके से उम्मीदवार चुने जा रहे थे। लोग कांग्रेस की वापसी चाहते हैं लेकिन यहां कांग्रेस के बड़े नेता गुटबाजी में लगे हुए हैं। मैंने हाई कमान से इसकी शिकायत भी कि इसे खत्म होना चाहिए लेकिन हाई कमान दोनों ग्रुप के प्रस्तावों से सहमत है।

140 सदस्यीय केरल विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव 2021 के लिए केरल में मतदान केंद्रों की संख्या को 21,498 से बढ़ाकर 40,771 कर दी गई है। मतों की गिनती 2 मई को होगी। 14वीं केरल विधानसभा का कार्यकाल 1 जून, 2021 को समाप्त होगा।

पीसी चाको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अपनी बयानबाजी के चक्कर में कई बार पार्टी के लिए सिरदर्द भी बन चुके हैं। पीसी चाको ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, यहां एक ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता का बने रहना मुश्किल हो रहा था। योग्यता की किसी कोई चिंता ही नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीसी चाको ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुए यासीन मलिक के समर्थन में बयान दे दिया था। हालांकि उन्होंने तुरंत ही खुद को ठीक कर लिया था।

खट्टर सरकार ने विश्वासमत जीता

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। सदन में बहुमत नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग के दौरान 32 सदस्य इसके पक्ष में खड़े हुए। वहीं, प्रस्ताव के खिलाफ में मनोहर लाल खट्टर को 55 विधायकों का समर्थन मिला। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

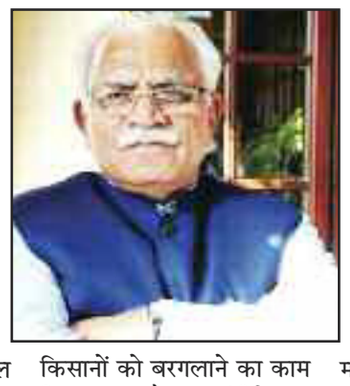

वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में प्रस्ताव पर चर्चा का अपना जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास राजनीतिक रोटियां सेंकने के अलावा और कोई मुददा नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष द्वारा लगातार किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन को उकसाने की बजाए इसे खत्म करवाने की पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। जब भी उन्हें कोई बात पसंद न आए तो वे अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि इनके अविश्वास का कारण हमारी निरंतर सफलता है, क्योंकि जनता के साथ हमारा गहरा विश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किए गये सभी जनहित के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी अविश्वास पैदा करती है। चुनाव आने पर ईवीएम पर इन्हें अविश्वास होने लगता है। वीर सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कांग्रेस ने स्वाल उठाकर सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अहंकार है जिससे उन्हें लगता है कि वे सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं या बना सकते हैं।

आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भाजपा-जजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सत्ताधारी दल ने लोगों का विश्वास खो दिया है।

मैं सबकी सेवा को तत्पर : ममता

मिदनापुर, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर की सबसे चर्चित सीट पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को इस सीट पर नामांकन करने के पहले नंदीग्राम के एक मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर सड़क किनारे एक टी स्टॉल पर जाकर ग्राहकों के लिए चाय बनाई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ममता बनर्जी टी स्टॉल पर चाय बांट रही हैं और खुद भी चाय की चुस्की ले रही हैं। यह पहला मौका नहीं है, जब ममता बनर्जी ने लोगों के बीच जाकर चाय की चुस्की ली हो, इससे पहले सन 2019 में भी उन्होंने चाय बनाई थी। उन्होंने खुद वीडियो जारी कर लिखा था कि कभी-कभी जीवन में छोटी खुशियां हमें खुश कर सकती हैं। कुछ अच्छी चाय बनाना और साझा करना उनमें से एक है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने पार्टी कार्यकताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ स्थानीय मजार में जियारत की और फिर नजदीक के मां चंडी मंदिर में प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह विभाजनकारी राजनीति में यकीन नहीं रखती हैं। ममता ने कहा कि मैं यहां सभी की सेवा के लिए हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने कहा कि शिवरात्रि पर मैं नंदीग्राम में मेरे घर के पास मंदिर में पूजा करुंगी। स्थानीय लोगों से बातचीत करूंगी और फिर अपना नामांकन दाखिल करूंगी। नंदीग्राम में उनका मुकाबला पूर्व करीबी सहयोगी और अब प्रतिद्वंद्वी शुभेंदु अधिकारी से है।

ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमला, पैर में चोट आई

विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमला किया गया। मौके से आए विजुअल्स में सिक्युरिटी गार्ड्स को 66 वर्षीय ममता को उठाकर पीछे की सीट में बैठाते हुए देखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, ममता के पैर में चोट आई है। ममता बनर्जी का नंदीग्राम में ही रात गुजारने के कार्यक्रम था लेकिन वे अब कोलकाता लौट आई हैं। ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यहां उनका मुकाबला अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से है।

तीसा मार्ग पर निजी बस खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत

चंबा । हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र तीसा में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। पुख्ता जानकारी के अनुसार बस में करीब 17 लोग सवार थे, इनमें से छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा 28 वर्षीय बस चालक की चंबा रेफर करते वक्त मौत हुई। हादसे में कुल नौ लोगों की मौत हुई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें चंबा अस्पताल में उपचाराधीन किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित विधानसभा उपाध्यक्ष एवं चुराह के विधायक हंसराज ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा हादसे में मृतकों के परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को भी हरसंभव मदद दी जाएगी।

चुराह के विधायक हंसराज विधानसभा की कार्यवाही को छोड़कर चंबा रवाना हो गए हैं। यह हादसा उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा हादसा उपमंडल मुख्यालय में काफी सवारियां उतारने के बाद हुआ है। पहले बस सवारियों से पूरी तरह से भरी हुई थी।

हादसा सुबह दस बजे के करीब हुआ। बताया जा रहा है तीसा के कॉलोनी मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कई लोग जिला मुख्यालय चंबा में अपने कामकाज के सिलसिले से आ रहे थे। इसके अलावा कॉलेज विद्यार्थी भी बस में सवार थे। हादसा इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस की छत यहां तक सीटें भी अलग-अलग होकर यहां वहां गिरी हैं।

खतरनाक चंबा-तीसा मार्ग पर चंबा की तरफ आ रही निजी बस कॉलोनी मोड से करीब 500 मीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त बस बुंदेडी से चंबा जा रही थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत खाई में उतर कर घायलों को सड़क तक पहुंचाया व वहां से अस्पताल पहुंचाया गया है।

पिछले वर्ष भी 10 मार्च को चंबा पठानकोट मार्ग पर बस हादसा हुआ था। एचआरटीसी की बस कांदू के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 34 लोग घायल हुए थे। एक साल बाद फिर दस मार्च को यह भयावह हादसा पेश आया है।

भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले मंत्री बने अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सेवारत (वर्तमान सरकार में भाजपा सांसद) और नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले मंत्री बन गए हैं। उन्हें जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट के रूप में टीए में कमीशन दिया गया था।

उपाधि मिलने के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया कि कुछ ही समय पहले संपन्न हुए प्रादेशिक सेना पिपिंग समारोह के बाद मैंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बात करने के बाद उनसे मिलने के लिए पहुंचा।

इससे पहले भारतीय सेना द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी को मानद उपाधि दी गई थी। देश को दी गई सेवा के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना ने 2010 में ग्रुप कैप्टन की मानद उपाधि से नवाजा था।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पैराशूट रेजिमेंट (106 पैरा टीए बटालियन) की प्रादेशिक सेना इकाई में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से नवाजा गया था। यह एक ऐसा सम्मान है, जिसे 2011 में सेना द्वारा दिया गया था। धोनी को यह सम्मान अभिनव बिंद्रा और दीपक राव के साथ दिया गया था, जो कि युद्ध का सामना करने के प्रमुख विशेषज्ञ थे।

अमृत महोत्सव व कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव में हों शामिल, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को दिए ये काम

नई दिल्ली, एजेंसी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर, प्रह्लाद पटेल समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक का आयोजन संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में किया गया। संसदीय कार्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आगे आने को कहा है।

एक साल बाद हुए इस संसदीय दल की बैठक में में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से अमृत महोत्सव के लिए सरकार की तैयारी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बैठक में सांसदों से बताया कि समारोह की शुरुआत 12 मार्च से होगी जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। समारोह का आयोजन गुजरात के साबरमती आश्रम में होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने समारोहों के आयोजन के लिए देश भर में 75 जगहों का चुनाव किया है।उन्होंने सांसदों से यह भी कहा कि इन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए वे अपने रायों में मौजूद रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में जारी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा करने में आगे आएं। उन्होंने कहा, जिस गति से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब एक ओर भारत होगा और दूसरी ओर दुनिया के तमाम देश। इसके अलावा उन्होंने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने व अनुशासन का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने चुनावी रायों के नेताओं को इसमें छूट दी और कहा, जिन नेताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में ड्यूटी दी गई है उन्हें छूट दी जा सकती है लेकिन अन्य की मौजूदगी अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में चार रायों व एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के रोडमैप पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना के कारण भाजपा संसदीय दल की बैठक एक साल से नहीं हुई थी। अंतिम बैठक पिछले साल 17 मार्च को हुई थी।

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की एक बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था। उन्होंन पार्टी के अछे कामों को लोगों तक पहुंचाने और चुनावों के मद्देनजर नेताओं पर निजी हमले करने से बचने की सलाह दी थी। इस बैठक में मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

अन्य देशों को वैक्सीन भेजकर भारत लगातार कर रहा मदद, अब जमैका और बेलीज़ की सहायता

किन्टाल। भारत सहित दुनिया के तमाम देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जंग के खिलाफ तमाम देशों में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। भारत दुनिया को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लगातार वैक्सीन देकर सहायता पहुंचा रहा है। अब सेंट्रल अमेरिका में स्थित बेलीज़में मेक इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाई गई है। उधर, कैरबियान आइसलैंड नेशन जमैका में भारतीय वैक्सीन भेजी गई है।

बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम भारत में 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इसके साथ ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ-साथ ब्राजील जैसे देशों को भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन भेजी है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) टेड्रोस अधनोम ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। महानिदेशक ने वैक्सीन भेजने के भारतीय प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से निपटने को लगातार सहयोग के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यावाद। इसके आगे महानिदेशक ने ट्वीट में लिखा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक-दूसरे से ज्ञान साझा करेंगे तो इस वायरस से लड़ सकते हैं। पिछले दिनों कोरोना टीकाकरण पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अपने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बजाय हम या तो वैक्सीन को दूसरे देशों को दान दे रहे हैं या फिर इसे बेच रहे हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार से टीकाकरण करने के लिए तय मापदंड को वर्गीकृत करने के पीछे का तर्क पूछा था। वहीं, सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया और भारत बायोटेक को अलग-अलग हलफनामा दायर कर बताने के लिए कहा है कि प्रतिदिन, प्रति सप्ताह से लेकर प्रति माह टीका निर्माण करने की उनकी क्या क्षमता है।

बाटा में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हुई, राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश

मालबा। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी के शहर बाटा में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि घटना के 48 घंटे बाद भी मलबे में शवों की तलाश जारी है। मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि विस्फोट में मरने वालों की संख्या शुरुआती अनुमानों से तीन गुना अधिक है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बच्चों को टूटी हुई कंक्रीट और मुड़ी हुई धातु के ढेर के नीचे से निकाला जा रहा है। इस रपिोर्ट के अनुसर चादर में लिपटे शव सड़क के किनारे पड़े हुए हैं।

राष्ट्रपति तियोदोरा ने घटना की जांच के आदेश दिए

उधर, इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति तियोदोरा ओबियांग नुमे ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति तियोदोरा ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डायनामाइट से निपटने में लापरवाही के कारण विस्फोट की घटना हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि विस्फोट में बाटा शहर के सभी इमारतों एवं घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। उनका अनुमान है कि इससे करीब 250,000 लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार की दोपहर सैन्य परिसर में चार विस्फोट हुए हैं। इन विस्फोटों ने गिनी के सबसे बड़ शहर और मुख्य आर्थिक केंद्र को हिला कर रख दिया। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमान लगाया गया था कि विस्फोटों में मरने वालों की संख्या 31 के आसपास होगी, लेकिन यह संख्या तीन गुना से अधिक निकल गई। मरने वालों में यहां के नागरकि और सैन्यकर्मी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उप-राष्ट्रपति पद का हवाला देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि इस घटना में कम से कम 615 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 299 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मरयम नवाज का आरोप, इमरान खान ने विश्वास मत के लिए दो सांसदों को कंटेनर में कराया था बंद

मालबा। इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्वास मत हासिल करने के लिए खुफिया विभाग की मदद से अपने दो मंत्रियों को चार घंटे तक कंटेनर में बंद करा दिया था।पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने पत्रकार वार्ता में यह दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने सांसदों को घेरने के लिए इमरान खान ने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। मरयम नवाज ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के सांसद उनके दल के संपर्क में हैं। साथ ही आरोप लगाया कि विश्वास मत हासिल करने के दौरान सरकारी एजेंसियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए उन्हीं के सांसदों को गायब करने का काम किया। मरयम नवाज ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के सांसद उनके दल के संपर्क में हैं। साथ ही आरोप लगाया कि विश्वास मत हासिल करने के दौरान सरकारी एजेंसियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए उन्हीं के सांसदों को गायब करने का काम किया। ज्ञात हो कि सीनेट के चुनाव में वित्तमंत्री के चुनाव हारने और विपक्ष के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग के बाद इमरान खान ने विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया था। पीएमएल-एन की नेता ने कहा कि इमरान खान के विश्वास मत प्राप्त करने को किसी भी रूप में वैध, संवैधानिक, राजनीतिक और नैतिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि विश्वास मत देने के लिए तैयार न होने वाले दो मंत्रियों को गोलरा (इस्लामाबाद के पास स्थान) में चार घंटे तक कंटेनर में बंद रखा गया। इमरान खान जानते थे कि ऐसा नहीं किया गया तो वह विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे।

कोरोना दुनिया में: नई स्टडी में दावा- ब्राजील में फैले नए स्ट्रेन पर अमेरिकी कंपनी फाइजर और चीनी कंपनी सिनोविक की वैक्सीन असरदार

ब्राजील। दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। दो अलग-अलग स्टडी में दावा किया गया है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और चीनी कंपनी सिनोविक की वैक्सीन ब्राजील में पाए गए कोविड के नए स्ट्रेन पर असरदार हैं।

न्यू इंग्लैंड जर्नल की लैब स्टडी में फाइजर का टीका नए Pv स्ट्रेन पर असरदार होने का दावा किया गया। यह स्ट्रेन सबसे पहले ब्राजील में पाया गया था। इससे पहले रिसर्चर्स ने यह टीका ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट पर भी असरदार पाया था। हालांकि, दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट पर इसका असर कुछ कम बताया गया था। उधर, ब्राजील में किए गए कुछ छोटे-छोटे अध्ययनों में चीनी कंपनी सिनोविक बायोटेक के टीके को क्का स्ट्रेन पर असरदार पाए जाने का दावा किया गया है।

अमेरिका में कोरोना के मामले 2.9 करोड़ के पार

अमेरिका में कोरोना के मामले 2 करोड़ 90 लाख के पार हो गए हैं। वहीं, वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5 लाख 25 हजार से ज्यादा हो गया है। सीएसएसई के आंकड़ों के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि यूएस राज्यों में कैलिफोर्निया में सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो कि इस वक्त 35.99 लाख है। टेक्सास में 26.95 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद फ्लोरिडा में 19.44 लाख और न्यूयॉर्क में 16.94 लाख मामले सामने आ चुके हैं।

मरीजों की संख्या 11.77 करोड़ से ज्यादा

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.77 करोड़ से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 26 लाख 12 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में 2.92 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 6 हजार से ज्यादा मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

महिला की मौत के बाद ऑस्ट्रिया में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सस्पेंड

वैक्सीनेशन के दौरान एक महिला की मौत के बाद ऑस्ट्रिया में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी रायटर्स ने यहां की हेल्थ एजेंसी के हवाले से बताया कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के बाद एक महिला की मौत हो जाने की वजह से एहतियात के तौर पर फिलहाल वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। संभावित साइड इफेक्ट्स को लेकर अन्य लोगों की जांच की जा रही है।

इजराइल में लॉकडाउन में ढील दी गई

इजराइली कैबिनेट की ओर से निर्णय लिए जाने के बाद देश में जारी लॉकडाउन में ढील दिए जाने के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया।

इस निर्णय के तहत देश में इजराइलियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, लेकिन रोज सिर्फ 3,000 लोगों को ही देश आने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही खुले स्थानों पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा नहीं हो सकेगी।

रिपब्लिकन पार्टी ने कहा, वह वित्तीय सहायता से संबंधित अपीलों में ट्रंप नाम का इस्तेमाल करती रहेगी

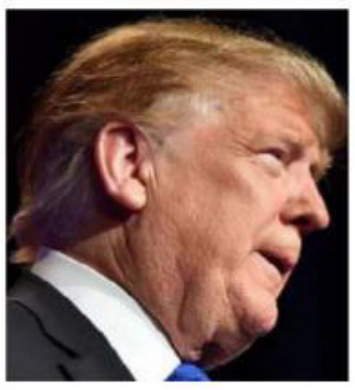

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी का इरादा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम का इस्तेमाल वित्तीय सहायता से संबंधित और अन्य सामग्रियों की फंडिंग में किया जाएगा। ऐसा पार्टी के एक वकील ने सोमवार को कहा। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी, नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस अभियान और नेशनल रिपब्लिकन सीनेट अभियान के लिए ट्रंप के लिए वकीलों द्वारा भेजे गए पत्र ने दो कैंप्स के बीच तनाव को बढ़ा दिया था क्योंकि ट्रंप चुनाव के बाद भी अपनी राजनीतिक व्यवहार्यता को बनाए रखना चाहते थे। ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि ट्रंप ब्रांडिंग के उद्देश्यों के लिए अपने नाम और समानता के उपयोग के प्रति संवेदनशील थे और वे तीन समूहों से नाराज थे, जिन्होंने रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन किया, लेकिन 6 जनवरी को स कैपिटल पर फैली अराजकता को लेकर महाभियोग की कार्रवाई में डेमोक्रेट्स में शामिल होकर मतदान करने लगे। वहीं, एक प्रतिक्रिया पत्र में, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने कहा कि ट्रंप ने सप्ताहांत में आरएनसी के चेयरमैन रोना मैकडैनियल को फिर से पुष्टि की कि वह अपने नाम के पार्टी के मौजूदा उपयोग को मंजूरी देते हैं, आरएनसी के शीर्ष वकील जस्टिन रिमेर ने लिखा बताया।

ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल बैन: अपने नागरिकों से मुंह मोड़ा, 40 हजार से ज्यादा दूसरे देशों में फंसे; बेघर और भूखे रह रहे

सिडनी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने देश की सीमाएं दूसरे देशों के लिए बंद कर दी थीं। लिहाजा जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और रेजिडेंट जिस देश में थे, वे वहीं फंस कर रह गए। इसके बाद सरकार कम संख्या में बाशिंदों को वापसी की इजाजत दे रही है।

इस समय 40 हजार से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई दूसरे देशों में फंसे हैं। इनमें से ज्यादातर की नौकरियां जा चुकी हैं। पैसे के लाले पड़ गए हैं और असमंजस यह है कि वतन लौट पाएंगे भी या नहीं। भास्कर ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की है।

30 साल से सिडनी में रह रहे दीपक 14 महीने से भारत में फंसे

1988 से सिडनी में रह रहे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक दीपक पूनिया 14 महीनों से भारत में फंसे हैं। 52 साल के दीपक जनवरी 2020 में अपने बीमार पिता की देख रेख के लिए गंगानगर आए थे। दीपक कहते हैं उनकी कम्पनी ने छुट्टियों के हिसाब से कुछ दिन तनख्वाह दी जो अब बन्द है। किसी तरह से बुजुर्ग पिता की सेविंग्स से गुजारा चल रहा है। वापस जाने के भी पैसे नहीं है।

सुजेन इंग्लैंड में होटल की साफ सफाई करके गुजारा कर रहीं

दीपक की तरह सुजेन भी साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड आई थीं। इरादा था घूमने और छोटा-मोटा काम कर यात्रा खर्च निकालने का था। अचानक 2020 में लॉकडाउन लगा। घूमना तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। सुजेन का कहना है कि उन्हें एक होटल में सफाई का काम मिला। वे एक साल से इसी होटल में हैं। काम के बदले रहने और खाने का इंतजाम हुआ है।

दो भाइयों की दुल्हनें भारत में फंसीं और दोनों ऑस्ट्रेलिया में

मेलबर्न निवासी दो भाइयों मनदीप और संदीप की कहानी तो और भी पेचीदा है। मनदीप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, जबकि संदीप परमानेंट रेजिडेंट। दोनों पिछले साल शादी करने हरियाणा के जींद गए। शादी के बाद दोनों मेलबर्न लौट गए, पर पत्नियां भारत में रहीं। तब से दुल्हनें भारत में, दूल्हे ऑस्ट्रेलिया में हैं।

देश की सीमाएं और ट्रैवल बैन 17 जून तक बढ़ा दिया

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सीमाएं 17 जून तक सील कर दी हैं। वायरस को रोकने के लिए ह्यूमन बायो सिक्युरिटी आपातकाल तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

डेनियल पर्ल हत्या मामले में पाकिस्तान के फैसले से हटा पर्दा

इस्लामाबाद। हाल में ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उमर सईद शेख को रिहा कर दिया था जो अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था। अल कायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख को कराची सेंट्रल जेल परिसर में बने रेस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। पर्ल के अपहरण से लेकर हत्या तक में शामिल सभी अपराधी उन आतंकी गुट के थे जिसे पाकिस्तान की ओर से समर्थन प्राप्त है। । शेख को रिहा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों में से दो ने बताया कि हत्या का आरोप गलत था और शेख ने पहले ही अपहरण मामले में अधिक समय की सजा भुगत ली थी। पर्ल मामले के रिपोर्टर असरा नोमानी ने स्पाइटॉक को यह जानकारी दी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सरकार को यह आदेश दिया था कि डेनियल के हत्यारे शेख को सेल से निकाल कर विश्राम गृह में रखा जाए। सूत्रों के अनुसार इन जजों का लिंक ढ्स्ढु से था। उल्लेखनीय है कि वाल स्ट्रीट जनरल के पत्रकार पर्ल कराची में लापता हो गए जिसके एक माह बाद 23 जनवरी 2001 में हत्यारों ने उनका सिर कलम करने वाला एक खौफनाक वीडियो पोस्ट किया था। इससे अमेरिका के साथ पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आ गया और यह भी पता चला कि दुनिया सबसे अधिक आतंकी गुट अलकायदा से अफगान तालिबान तक को भारत में खूनी हमलों को अंजाम देने वाली आतंकवादी इकाइयों के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा एजेंसियों को कैसे इस्लामाबाद ने सशक्त किया।वर्ष 2002 में कराची में पर्ल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ढ्स्ढु और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे और तभी उनका अपहरण हो गया था। इसके बाद सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी।

विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तान से दो टूक कहा था कि वह शेख की रिहाई रोके वरना अमेरिका खुद उसे सजा देगा। पर्ल के हत्यारे की रिहाई के आदेश की आलोचना करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि वाशिंगटन एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ खौफनाक गुनाहों के लिए उमर शेख के खिलाफ अपने यहां मुकदमा चलाने को तैयार है।

साइनस सर्जरी वाले कोरोना की जांच के लिए नेजल सैंपल देने में रहें सतर्क, ईएनटी डॉक्टर से करें परामर्श

वाशिंगटन। कोरोना की जांच के लिए नाक से टेस्ट सैंपल (नेजल स्वैब) लेना एक आम तरीका है। दुनियाभर में यह प्रचलित भी है। लेकिन एक हालिया शोध में इसके लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। खासकर जिन लोगों की साइनस सर्जरी हुई है, उन्हें तो नेजल सैंपल देने से पहले ईएनटी (कान, नाक और गले) के डॉक्टर से परामर्श लेने या जांच का कोई दूसरा तरीका अपनाने को कहा गया है।

'जामा ओटोलरिंगोलॉजी' नामक एक जर्नल में प्रकाशित शोध आलेख के वरिष्ठ लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के सैन एंटोनियो स्थित हेल्थ साइंस सेंटर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. फिलिप जी. चेन का कहना है कि जो लोग नेजल स्वैब सैंपल लेते हैं, उन्हें रोगी से यह जरूर पूछना चाहिए कि क्या उनकी साइनस या स्कल सर्जरी हुई है। यदि ऐसा है तो जांच के दूसरे तरीके अपनाए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में गले से स्वैब लिया जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि नेजल स्वैब लेने से पहले न तो रोगी से इस बारे में सवाल किए जाते हैं और न ही इस संबंध में ऑनलाइन सूचना उपलब्ध है।

उन्होंने कहा, हमने करीब 200 साइटों पर इसके बारे में सूचना हासिल करने की कोशिश की कि क्या कहीं भी नेजल सैंपल लेने में बरती जानी सतर्कता बताई गई है। लेकिन हमें कहीं भी वैसा ब्योरा नहीं मिला, जिसमें रोगी से साइनस या मस्तिष्क (स्कल) से जुड़ी सर्जरी के बारे में उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश की गई हो।

यह पूछे जाने पर कि स्वैब लेने क्या गलत तरीका अपनाया जाता है, डॉ. चेन ने बताया, हम यह तो नहीं जानते, लेकिन हमने जितने ऑनलाइन वीडियो देखे उनमें से आधे में कुछ न कुछ गलत पाया। इनमें पाया गया कि स्वैब या तो गलत एंगल या गहराई से उठाया गया। यदि स्वैब को बड़े एंगल से उठाया गया तो इस प्रक्रिया में खतरा बना रहता है,

क्योंकि हो सकता है कि उस एंगल पर साइनस स्कल की सुरक्षा कर रहा हो और स्वैब लेने में वह पंक्चर हो जाए। इसमें इसका भी डर बना रहता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (मस्तिष्क में पाया जाना वाला खास प्रकार का द्रव) लीक हो जाए या ज्यादा रक्त स्नाव हो जाए। ऐसा होना खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है।

यूके की संसद में गूंजा किसानों का मुद्दा: ब्रिटिश मंत्री बोले- किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मसला; भारत ने आपत्ति जताई, कहा- झूठे तथ्यों के आधार पर चर्चा हुई

ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद में एक बार फिर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का मुद्दा गूंजा। यूके ने दोहराया कि कृषि सुधार कानून भारत का घरेलू मामला है और लोकतंत्र में सुरक्षा बलों को कानून-व्यवस्था लागू करने का अधिकार है। दरअसल, ब्रिटिश संसद के वेस्टमिंस्टर हाल में हुई इस चर्चा में 18 ब्रिटिश सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 17 ने आंदोलन का समर्थन किया। लेबर पार्टी ने इस चर्चा की मांग की थी।

विदेशी संसद में हुई चर्चा पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग ने कहा है कि चर्चा के दौरान सांसदों ने झूठे तथ्य पेश किए। हमें इस बात का अफसोस है कि चर्चा के दौरान संतुलित बहस के बजाय झूठे दावों और बिना किसी तथ्यों के आधार पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया (जिसमें ब्रिटिश मीडिया भी शामिल है) भारत में मौजूद है और सभी ने आंदोलन के हल के लिए की गई बातचीत को देखा है। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता की कमी का सवाल ही नहीं उठता।

ब्रिटिश मंत्री बोले- शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार लोकतंत्र में अहम

यूके में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एशिया निगेल एडम्स ने कहा कि कृषि नीति भारत सरकार के लिए एक आंतरिक मसला है। हमारी सरकार का दृढ़ता से मानना है कि बोलने की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि कोई विरोध-प्रदर्शन अपनी लिमिट क्रॉस करता है, तो लोकतंत्र में सुरक्षा बलों को कानून-व्यवस्था लागू कराने का अधिकार है। एडम्स ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में 'भारत में शांतिपूर्ण विरोध और प्रेस की आजादी' के मुद्दे पर एक बहस के दौरान यह बयान दिया।

बातचीत के जरिए हल निकलने की उम्मीद

उन्होंने कहा कि भारत में हमारे हाईकमीशन नेटवर्क के अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कृषि

कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर हमें लगातार फीडबैक दे रहे हैं। हमें पता है कि भारत सरकार ने मामले को हल करने के लिए कई बार किसानों से बात भी की है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मामले का हल बातचीत के जरिए ही निकाल लिया जाएगा।

ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई

ब्रिटेन की संसद में यह चर्चा एक पिटीशन के बाद हुई। इसमें ब्रिटिश सरकार से अपील की गई है कि वो आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा और प्रेस फ्रीडम को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाए। पिटीशन नवंबर महीने में लाई गई, जिस पर करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने साइन किए थे।

किसान आंदोलन को लेबर पार्टी का समर्थन

कोविड प्रोटोकॉल के चलते कुछ सांसदों ने घर से ही डिजिटल माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। कुछ सांसद पार्लियामेंट में मौजूद रहे। किसान आंदोलन को सबसे अधिक लेबर पार्टी का समर्थन मिला। लेबर पार्टी के 12 सांसदों जिसमें लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कोर्बीन भी शामिल थे। कोर्बीन ने इससे पहले भी किसानों का समर्थन किया था।

विदेशी संसद में चर्चा नहीं हो सकती : विलियर्स

इसी दौरान कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा विलियर्स ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि भारत का अपना आंतरिक मामला है, इसके ऊपर विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

भारत में 100 दिन से ज्यादा से जारी आंदोलन

भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 100 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीन नए कृषि सुधार कानूनों को पूरी तरह वापस लिया जाए। सरकार ने कानूनों में संशोधन की बात कही थी, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा की कुंडली बॉर्डर पर बैठक

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को होने वाली बैठक आज ही बुला ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार, मीटिंग शुरु हो गई है। बैठक में डॉ दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, बलदेव सिरसा और मनजीत राय समेत कई लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में सरकार से वार्ता के लिए कमेटी बनाने की बात सामने आने और इसको लेकर आंदोलनकारियों में उपजे विवाद के बाद मोर्चा ने आज ही बैठक बुला ली है। बैठक में सरकार पर बातचीत को लेकर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इससे पहले मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह फूल ने बताया कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बार्डर पर साढ़े तीन माह से आंदोलनकारी जीटी रोड को जाम करके बैठे हैं। 22 जनवरी को मोर्चा के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हुई थी। सरकार कानूनों को लंबित रखने और इसमें संशोधन का प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन मोर्चा के नेता इसे पूरी तरह से रद कराने पर अड़े हैं। इसके कारण बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ 100 से ज्यादा दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल धरना स्थल पर लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए यहां पर पंखे व कूलर लगा दिए गए हैं। 103 दिन से प्रदर्शनकारी रोज धरने पर आकर बैठते हैं और भोजन कर वापस लौट जाते हैं। यहां पर आधे से ज्यादा वक्ता तो ऐसे होते हैं जिनको धरने पर बैठे लोग जानते भी नहीं हैं। बस नारेबाजी के दौरान ही वह एक साथ दिखाई देते हैं। सिंघु बार्डर पर दिल्ली की सीमा में धरना स्थल के पास गर्मी से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने पराली के टेंट बनाए हैं।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में खुद को बताया हनुमान भक्त

अयोध्या में मंदिर बन जाने पर दिल्ली के सभी बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन कराऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछले 5-6 सालों में शिक्षा क्षेत्र में जो काम हुआ है उसे क्रांति के रूप में देखा जा रहा है।

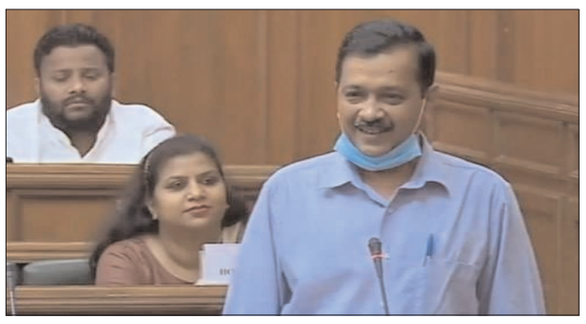

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को भगवान राम और हनुमान का भक्त बताया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के राज्य में सभी जनता सुखी थी। भगवान राम की अयोध्या की तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार राम राज्य लाना चाहती है। उसी दिशा में काम किया जा रहा है। हम जनता के हित से जुड़े हर कार्य को कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम शिक्षा के बेहतर करना चाहते हैं। दिल्ली के हर आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं। चाहें कोई कितना भी गरीब क्यों न हो। आज दिल्ली दुनिया का अकेला शहर है जहां सभी को 24 घंटे पानी मिलता है। गरीबों को मुफ्त बिजली मिलती है। सभी को पूरा और साफ पानी मिले। सभी के पास मकान हो। गरीब के पास भी पक्के मकान हों। महिलाओं को सुरक्षा मिले। सदन में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। जो समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे सकता, उसका अंत निश्चित है। हमने उनके लिए तीर्थयात्रा की व्यवस्था शुरू की है। अयोध्या में मंदिर बन जाने पर दिल्ली के सभी बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन कराऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछले 5-6 सालों में शिक्षा क्षेत्र में जो काम हुआ है उसे क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चे भी फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं, वे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रहे हैं। बता दें कि यह पहला मौका नही है जब सीएम केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त बताया हो। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी वह हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं और हनुमान मंदिर जा चुके हैं। भारी बहुमत आने पर भी वह परिवार के साथ हनुमान जी का आशींवाद लेने मंदिर गए थे।

शिवरात्रि पर मां झंडेवाली के भक्तों को मिलेगा शिवालय

झंडेवाला देवी मंदिर में शिवालय की सौगात मिलने जा रही है

नई दिल्ली। राजधानी में रहने वाले भगवान महादेव के भक्तों को इस महाशिवरात्रि पर झंडेवाला देवी मंदिर में शिवालय की सौगात मिलने जा रही है। दरअसल, झंडेवाला देवी मंदिर में आने वाले भक्त लंबे समय से शिवालय की मांग कर रहे थे। यह अब डेढ़ साल बाद जाकर बनकर तैयार हो गया है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी रात्रि में लोग मंदिर में रुद्राभिषेक नहीं कर सकेंगे। हालांकि इस साल झंडेवाला देवी मंदिर में भक्त मंदिर से ही मिले पंचामृत से भगवान आशुतोष का अभिषेक कर सकेंगे। यह व्यवस्था मंदिर समिति की ओर से की गई है। झंडेवाला मंदिर के प्रबंधक रविंद्र गोयल ने बताया कि महाशिवरात्रि की समिति की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। फूलों से सजावट की गई है। विशेष शिवलिंग के साथ ही अन्य व्यवस्था भी शिवालय में की गई हैं, जिसमें भक्तों को रुद्राभिषेक के लिए जल और लोटे की व्यवस्था मंदिर की ओर से की गई है। घर से जल, दूध व लोटा लेकर आने वाले भक्तों को शिवरात्रि पर प्रवेश पर रोक रहेगी।

प्रबंधक ने बताया कि मंदिर में सुबह से लेकर रात महादेव के जयकारों के साथ भजनों की भी धूम रहेगी। बालीवुड के मशहूर गायक शंकर साहनी भी मंदिर में आकर भगवान के भजनों का गुणगान करेंगे।

कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा महादेव के भक्तों के लिए दिल्ली का गौरी शंकर, प्राचीन हनुमान मंदिर, मरघट वाले बाबा का मंदिर समेत अन्य मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सभी मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। गौरी शंकर मंदिर के पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना के कारण भक्तों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, वहीं भक्तों को कतार में रहकर ही मंदिर तक प्रवेश मिलेगा। झंडेवाला मंदिर में शिवालय की शुरुआत के साथ ही भक्तों के प्रसाद के लिए विशेष प्रबंध इस साल किया गया है। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए मंदिर प्रबंधन ने सील पैक प्रसाद की योजना बनाई है। सुबह भक्तों को सील पैक पंचामृत मिलेगा। इसके बाद सील पैक डिब्बे वाली आइसक्रीम भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाएगी। रविंद्र गोयल ने बताया कि चार पहर के रुद्राभिषेक के बाद भक्तों को सील पैक भोजन भी प्रसाद के रूप में दिया जाएगा, वहीं व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को फल व अन्य प्रसाद दिया जाएगा। प्रबंधक ने बताया कि मंदिर में सुबह से लेकर रात महादेव के जयकारों के साथ भजनों की भी धूम रहेगी। बालीवुड के मशहूर गायक शंकर साहनी भी मंदिर में आकर भगवान के भजनों का गुणगान करेंगे। सुबह आठ बजे से दिन में चार बजे तक मंत्रों का उच्चारण भी परिसर में किया जाएगा। वहीं, मां झंडेवाली के भवन को फूलों से सजाया जाएगा, ताकि महादेव के दर्शन के साथ ही भक्त मां के दर्शन भी कर सकेंगे।

नई बसें बनाएंगी दिल्लीवासियों का सफर आसान

नई दिल्ली। दिल्लीवासियों के सफर को आसान और आरामदायक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बजट में इस साल कुल 2,300 बसें सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा परिवहन विभाग, सड़क और पुलों के लिए 9,394 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। सार्वजनिक परिवहन के तहत बसों का बेड़ा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए 1,300 ई-बसें सड़कों पर लाने की तैयारी की जा रही है। इनमें से डीटीसी के लिए 300 ई-बसों के टेंडर हो चुके हैं। ये बसें इसी वर्ष दिसंबर तक सड़कों पर उतर जाएंगी। 1,000 नई ई-बसें क्लस्टर स्कीम के तहत दिसंबर से अगले साल के मध्य तक सड़कों पर आ जाएंगी। दिल्ली में पहली बार एक साल के अंदर 1,600 बसों का काफिला जुड़ा है। इस साल सितंबर तक इसमें 1,000 और बसें जुड़ जाएंगी।

आतंकियों की मौजूदगी की बात और साक्ष्य सही- कोर्ट

नई दिल्ली। सियासी चक्रव्यूह में फंसाकर बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दिल्ली पुलिस पर भले ही तमाम सवाल उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) आतंकियों की घटनास्थल पर मौजूदगी से लेकर वहां हुई बरामदगी को साकेत कोर्ट ने सही ठहराया है। साकेत कोर्ट ने बचाव पक्ष की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और सुबूतों पर सवाल उठाए गए थे।

बचाव पक्ष की यह भी दलील थी कि जांच अधिकारी सतीश शर्मा ने क्रास-एक्जामिनेशन में कहा था कि जब एक अक्टूबर 2008 को जांच उन्हें सौंपी गई तब इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं थी।

बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष के अनुसार पूरी घटना दो से तीन मिनट की थी। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के लिए आरोपितों का चेहरा पहचानना संभव नहीं है और अदालत में आरोपितों की पहचान करना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

बचाव पक्ष ने कहा था कि प्रवेश और निकास का एक ही रास्ता होने के कारण बिल्डिंग से कोई भाग नहीं सका था। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष को यह दिमाग में रखना चाहिए कि आरोपित सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्हें इस तरह की परिस्थितियों में भागने का प्रशिक्षण दिया गया था। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मामले की जांच कर रहे पहले जांच अधिकारी इंस्पेक्टर जेएस जून को फ्लैट से बरामद किए गए पर्स और शैक्षणिक दस्तावेज की जानकारी नहीं दी गई थी और इसे बाद में प्लांट किया गया था। बचाव पक्ष की यह भी दलील थी कि जांच अधिकारी सतीश शर्मा ने क्रास-एक्जामिनेशन में कहा था कि जब एक अक्टूबर 2008 को जांच उन्हें सौंपी गई तब इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं थी। वहीं पांच जनवरी 2009 को तत्कालीन एसीपी संजीव कुमार यादव ने अपने बयान में पर्स और फोटोग्राफ की जानकारी दी थी। इस पर अदालत ने कहा कि संभव है कि एसीपी के स्तर पर जांच अधिकारी के समक्ष बरामदगी की जानकारी देने में देरी हुई, लेकिन देरी होने से विरोधाभास नहीं पैदा होता है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष के अनुसार पूरी घटना दो से तीन मिनट की थी। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के लिए आरोपितों का चेहरा पहचानना संभव नहीं है और अदालत में आरोपितों की पहचान करना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अदालत ने इस पर कहा कि घटनास्थल पर मौजूद रहे और गंभीर रूप से घायल हुए हवलदार बलवंत सिंह आरोपित की गलत पहचान नहीं करेंगे। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस ने मामले में भवन स्वामी से लेकर किसी भी पड़ोसी का पक्ष नहीं लिया। इसके जवाब में कहा गया कि आरोप पत्र में पुलिस ने व्यक्तिगत गवाह तलाश करने के लिए प्रयास किए, लेकिन घटनास्थल का कोई भी व्यक्ति जांच में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ।

आरके पुरम थाने ने उठाया अनूठा कदम, महिलाओं के लिए लगाया सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण-पश्चिमी जिले के आरके पुरम थाने में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर लगाया गया। ऐसा करने वाला यह दिल्ली का पहला पुलिस थाना बन गया है। इस डिस्पेंसर से थाने के स्टाफ के साथ ही कोई भी महिला या व्यक्ति सैनिटरी नैपकिन प्राप्त कर सकता है। यह नैपकिन बाजार दर से काफी कम में यानि पांच रुपये प्रति पीस मिलेगा। दरअसल, कोई इस सुविधा का दुरुपयोग न करे, इसलिए यह शुल्क रखा गया है। सोमवार को बतौर मुख्य अतिथि नई दिल्ली रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त जसपाल सिंह ने इस डिस्पेंसर का उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमित गोयल व अमित कौशिक भी मौजूद रहे। एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि थाने के आसपास कई झुग्गियां हैं जहां गरीब महिलाएं रहती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के परिवार में लोग आज भी इस विषय पर बात नहीं करते हैं। इन घरों की महिलाएं मेडिकल स्टोर पर सैनिटरी नैपकिन लेने जाने में झिझकती हैं। संगिनी सहेली एनजीओ की संस्थापक प्रियल भारद्वाज ने उन्हें यहां पर डिस्पेंसर लगाने में सहयोग किया।

पंजाब में बड़े सिख धर्मगुरु की हत्या की रच रहे थे साजिश, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के के बाद से ही देश विरोधी ताकतें लगातार किसी ना किसी साजिश को अंजाम देने में लगी हुई हैं। पहले लाल किले पर हिंसा कर देश की छवि को खराब करने की साजिश रची गई फिर ग्रेटा थनबर्ग द्वारा टूल किल मामला सामने आया। इसी कड़ी में अब एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो पंजाब और हरियाणा में बड़ी अशांति फैलान की साजिश रच रहे थे। इन दोनों मिलकर पंजाब में किसी बड़े निहंग लीडर की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। इससे पहले ही यह बात पुलिस को पता चल गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या कर यह माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो निहंग सिख को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम मलकियत सिंह और जबरजंग हैं। पुलिस से शुरुआती मिली सूचना में यह बताया गया है कि इन दोनों का लाल किले की हिंसा में हाथ है या नहीं है यह पता नहीं लेकिन इसकी जांच की जा रही है। इन दोनों को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दोनों एक सिख धर्मगुरु की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से जिस निहंग को पकड़ा गया है वो कुछ दिन पहले ही दिल्ली के तिहाड़ जेल से पेरोल पर बाहर आया है। जबरजंग को स्पेशल सेल ने क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है क्राइम ब्रांच जांच करेगी कि क्या इसका लाल किला हिंसा में कोई रोल है या नहीं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी दोनों को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन कोरोना के चलते अदालत ने दोनों को पैरोल दे दी थी। जबरजंग सिंह लक्खा सिधाना का काफी करीबी बताया जाता है। स्पेशल सेल के मुताबिक ये दोनों भूपेंद्र नाम के एक शख्स के साथ मिलकर सिख गुरु की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। भूपेंद्र को भी सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे विस्तार से पूछताछ में यह खुलासा होगा कि आखिर किसके कहने से यह पूरा खेल रचा गया और किस सिख गुरु की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे।

बता दें कि किसान आंदोलन के कारण हरियाणा और पंजाब के कई सिख दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। यहां पर केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। किसानों ने यह पहले ही बता दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक यह आंदोलन चलेगा।

न्याय पालिका लोकतंत्र का एक स्तंभ, दूसरों से तुलना करना सही नहीं : हाई कोर्ट

नई दिल्ली। केंद्र ने कोरोना टीके से संबधित एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि टीका पेशे के हिसाब से नहीं, बल्कि महामारी की चपेट में आने के लिए चयनित की गई अलग-अलग उम्र की श्रेणी के हिसाब से लगाया जा रहा है। बार कार्उसिल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायाधीश, अधिवक्ताओं और अदालत के कर्मचारियों को टीका लगाने की मांग की थी।

इस पत्र को हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने न्यायमूर्ति विपीन सांघी की पीठ को बताया कि टीकाकरण को पेशे के हिसाब से नहीं बांटा गया है। बल्कि की विशेषज्ञों ने जो उम्र की अलग-अलग श्रेणियां बांटी हैं, उसके मुताबिक टीकाकरण किया जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि न्याय पालिका लोकतंत्र का एक स्तंभ है और इसकी तुलना अन्य किसी पेशे के साथ नहीं की जा सकती। रोजाना अदालतों में तरह-तरह के हजारों लोग आते हैं और ऐसे में यह नही का जा सकता कि यहां महामारी बेअसर हो चुकी है।

सालिस्टिर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार के शपथ से साफ जाहिर है कि नागारिकों के स्वास्थ्य को लेकर कितने गंभीर हैं। भारत अन्य देशों के मुकाबले टीकाकरण में कहीं आगे है। उन्होंने पीठ को स्पष्ट किया कि वे एक पेशे से दूसरे की तुलना नहीं कर रहे हैं। सरकार ने तीनों स्तभों में कार्यरत अलग-अलग उम्र की श्रेणियां बनाई हैं और किसी भी तरह से एक पेशे की दूसरे से तुलना नहीं की है। पीठ को बताया गया कि ऐसी ही एक अन्य याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उस पर 15 मार्च को सुनवाई हो सकती है। ऐसे में पीठ से गुजारिश है कि इस याचिका को बाद में सुना जाए। इस पर पीठ ने सुनवाई 19 मार्च के लिए टाल दी।

दिल्ली में चोरी करने गए शख्स के ऊपर गिरा लोहे का गार्टर व छज्जा, चली गई जान

नई दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में सोमवार देर रात निर्माणाधीन मकान में चोरी करने के लिए गए एक शख्स की लोहे के गार्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है। मनोज अपने एक साथी के साथ मकान में चोरी करने के लिए गया था, दीवार के सहारे लोहे के गार्टर खड़े थे।

जब दोनों ने उन्हें चोरी करने की कोशिश की तो लोहे का एक गार्टर व छज्जे का कुछ हिस्सा मनोज के ऊपर गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा खिचड़ीपुर के दो-ब्लाक में रहने वाले राजीव कुमार के मकान में हुआ।

पुलिस के अनुसार, राजीव के मकान का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। मकान के छज्जे की सपोर्ट के लिए लोहे के गार्टर लगाए हुए थे, साथ ही कुछ और गार्टर दीवार के सहारे रखे थे।

सोमवार रात को खिचड़ीपुर झुग्गियों का रहने वाला मनोज अपने साथी के साथ चोरी के लिए मकान में पहुंचा। दोनों ने जैसे ही सपोर्ट के लिए लगे गार्टर को हटाया अचानक छज्जा और गार्टर मनोज के ऊपर गिर गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने बताया कि घटना की शुरुआत में पता नहीं चल रहा था कि मनोज वहां कैसे पहुंचा, पुलिस ने जब एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उससे साफ हो गया कि वह चोरी के इरादे से मकान में आया था।

सिंघु बॉर्डर पर दिखा भेदभाव का नजारा, अमीर-गरीब प्रदर्शनकारी के बीच पैदा हो रही खाई

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर दिल्ली-एनसीआर के चारों बॉर्डर (सिंघु, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर) पर किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी है। पिछले तीन महीने से भी अधिक समय से चल रहा किसानों का धरना अब विवादों में पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल, सिंघु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 100 से ज्यादा दिनों से जारी विरोधी प्रदर्शन में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, यहां भेदभाव भी देखने को मिलने लगा है। यह भेदभाव है अमीर और गरीब तबके के प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई दे रहा है। यहां कोई प्रदर्शनकारी एसी की ठंडी हवा में बैठकर शाही तरीके से कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी भी यहां नजर आ रहे हैं जिन्हें टेंट पर पराली की छत बनाकर गर्मी को मात देनी पड़ रही है। कोई यहां लग्जरी गाड़ियों में घूमने आ रहा है तो कोई ट्राली के नीचे दोपहर गुजार रहा है। गरीब तबके के प्रदर्शनकारियों के टेंट में पंखे लगे हुए हैं, जबकि अमीरों के टेंटों में एसी। गरीबों के टेंटों में पानी की बोतलें रखी हैं, जबकि अमीर प्रदर्शनकारियों के टेंटों में ठंडे पेय की भी सुविधा है। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए प्रदर्शनकारी अब झोपड़ीनुमा टेंट बनाने लगे हैं। इन टेंटों में प्लास्टिक के टेंटों के मुकाबले कम गर्मी लगती है। इसलिए वह इसी का इस्तेमाल करते नजर आने लगे हैं। दरअसल धरना स्थल पर लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए यहां पर पंखे व कूलर लगा दिए गए हैं। 103 दिन से प्रदर्शनकारी रोज धरने पर आकर बैठते हैं और भोजन कर वापस लौट जाते हैं। यहां पर आधे से ज्यादा वक्ता तो ऐसे होते हैं जिनको धरने पर बैठे लोग जानते भी नहीं हैं। बस नारेबाजी के दौरान ही वह एक साथ दिखाई देते हैं। उधर, दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक बुधवार को ही दोपहर बाद तीन बजे के करीब होगी।

अरविंद केजरीवाल ने की गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ

कहा- कोरोना काल में बेहतर काम किया

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान किए गए कामों को सराहा। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना काल कठिन समय था। ऐसे समय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी बेहतरीन काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान राजधानी आम आदमी पार्टी सरकार ने जनता के साथ मिलकर बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि जिस भी तरीके से सरकार जनता की सेवा कर सकती थी, सरकार ने की। इस दौरान सभी ने बेहतर काम किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने बेहतर काम किया है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अमित शाह ने ताबड़तोड़ बैठकें करके कई अहम कदम उठाए थे। इसके बाद कोरोना के मामलों में कमी भी आई थी। सदन में अपनी बात रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायकों ने भी बेहतर काम किया है। यह संकट इतना बड़ा था कि किसी एक सरकार के बस की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि डाक्टरों ने सबसे बेहतर काम किया। वह नहीं करते तो सब कैसे होता। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक स्कूल में निरीक्षण करने गए तो उस कक्षा में दिख रहा था कि 12 कुर्सियां ही थीं। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे आप खुद समझ रहे होंगे। दूसरे राज्यों के नेताओं को स्कूलों में क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा दिल्ली सरकार के कारण हो रहा है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इससे कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने गए थे। उससे योगी आदित्यनाथ जो को भी लगा कि हमें भी अपने स्कूल देख लेना चाहिए कि स्कूलों की उन्होंने क्या हालत कर रखी है।

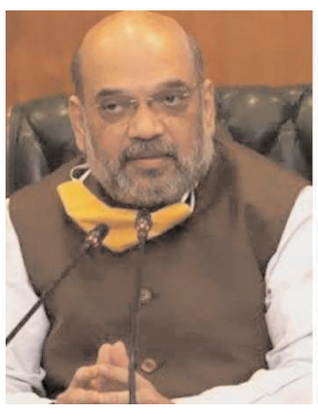

युवक ने बनाया नया साफ्टवेयर, घर बैठे उठा सकते हैं अपने वाहन से जुड़ी सुविधा का लाभ

पश्चिमी दिल्ली। व्यस्त जीवनशैली के बीच समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग व रखरखाव किसी परेशानी व तनाव से कम नहीं है। सप्ताह में मिलनी वाली एक छुट्टी इसी काम में निकल जाती है। इसका बड़ा कारण है कि लोग अपनी आंखों के सामने अपने वाहन की सर्विसिंग देखना चाहते हैं ताकि सर्विसिंग के दौरान किसी खराब सामान का इस्तेमाल न हो। इस परेशानी को अनुभव करने के बाद नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व विद्यार्थी अभिजीत पाठक(24) ने इस पर अपने स्टार्टअप की नींव रखी और मैकवाहन एप व पोर्टल डिजाइन किया, जहां एक ही प्लेटफार्म पर वाहन से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें वाहन की सर्विसिंग, मरम्मत, बीमा व खरीदने-बेचने तक की सुविधा है। अभिजीत ने बताया कि लोग घर बैठे-बैठे मोबाइल पर सर्विसिंग लाइव देख सकते हैं। सर्विसिंग के लिए वाहन को घर से ले जाने व छोड़ने की सुविधा भी इस एप व पोर्टल पर उपलब्ध है। जिस तरह घर बैठे-बैठे एप की मदद से आपका मनपसंद खाना घर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार अब वाहन की सर्विस कराना भी मैकवाहन की मदद से सरल हो गया है। सात माह पहले मार्केट में लांच हुआ मैकवाहन एप फिलहाल दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, पटना, जयपुर, जोधपुर, रांची, लखनऊ में अपनी सर्विस उपलब्ध करा रहा है। जहां 100 सर्विस स्टेशन को जोड़ा गया है। सभी सर्विस स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित मानक के अनुरूप ट्रेनिंग दी गई है ताकि गुणवत्ता को लेकर ग्राहक को शिकायत न हो। अब तक ढाई हजार लोग इसका लाभ ले चुके हैं। सभी ने मैकवाहन की सर्विस को सराहा है। मैकवाहन को 51 शहरों में लांच करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अभिजीत बताते हैं कि इस काम में सफलता में उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें मृदुल वर्मा, संजीव कुमार, अभिषेक दिव्यदर्शी, विवेक गुप्ता, सूरज कुमार व रतनेश भारद्वाज शामिल हैं।

संपादकीय

नौकरी नहीं, तो आरक्षण ही सही

हरियाणा सरकार के एक फैसले से हंगामा खड़ा हो गया है। फैसला है रोजगार में आरक्षण का। रोजगार भी सरकारी नहीं, प्राइवेट और आरक्षण भी किसी जाति, धर्म या आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि राज्य में रहने वालों को। राज्य सरकार ने यह फैसला अपने लोगों की भलाई या उन्हें खुश करने के लिए लिया है। लोग खुश हुए या नहीं, इसका पता तो चुनाव में लगेगा और उनकी कितनी भलाई हुई, इसका पता लगने में भी काफी वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल इस फैसले से हंगामा खड़ा हो गया है। खासकर हरियाणा में जिन कंपनियों की फैक्टरियां या दफ्तर हैं, उनमें गंभीर चिंता फैल गई है। हरियाणा में प्राइवेट कारोबार में भी 50 हजार रुपये महीने से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत पर सिर्फ हरियाणा के लोग रखे जा सकेंगे। विधानसभा में तो यह विधेयक पहले पारित हो चुका था, 28 फरवरी को राज्यपाल ने भी दस्तखत किए हैं। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने घोषणापत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी, तो 75 फीसदी नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित करवाएगी। उद्योग और विकास के पैमाने पर हरियाणा देश के सबसे उन्नत राज्यों में रहा है, लेकिन इस वक्त बेरोजगारी बहुत बड़ी फिक्र है। सीएमआईई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जहां पूरे देश में बेरोजगारी दर फरवरी महीने में 6.5 प्रतिशत थी, वहीं हरियाणा में 26.4 प्रतिशत पर थी। यानी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। जाहिर है, राज्य सरकार परेशान है। लेकिन आरक्षण की यह कोशिश नुकसान पहुंचा सकती है। देश के दोनों प्रमुख उद्योग संगठनों फिक्की और सीआईआई ने इस पर चिंता जताई है। सीआईआई ने आग्रह किया है कि पुनर्विचार किया जाए, जबकि फिक्की ने कहा है कि यह फैसला प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए तबाही जैसा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी और बीपीओ कंपनी जेनपैक्ट के अलावा सॉफ्टवेयर व टेक्नोलॉजी में देश-दुनिया की दिग्गज कंपनियों ने गुड़गांव में दफ्तर खोल रखे हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टीसीएस और इंफोसिस जैसे नाम शामिल हैं। यह नया कानून इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। बीपीओ या बीपीएम कारोबार एक तरह से गुड़गांव की जान है। गुड़गांव को दुनिया की बीपीएम राजधानी भी कहा जाता है। दुनिया में इस काम में लगे लोगों का पांच प्रतिशत हिस्सा गुड़गांव में है। बीपीओ व आईटी कंपनियों के अलावा गुड़गांव और मानेसर के इलाके बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। देश की 50 प्रतिशत कारें, 60 प्रतिशत मोटरसाइकिलें और 11 प्रतिशत ट्रैक्टर यहीं पर बनते हैं। इन इलाकों में औद्योगिक विकास के साथ ही यूनियन और मैनेजमेंट के विवाद का भी लंबा इतिहास है। 2012 में मारुति के प्लांट में झगड़ा इतना विकराल हो गया था कि आंदोलनकारियों ने कंपनी के एक बड़े अफसर को जलाकर मार डाला था। उसके बाद से ही कंपनी ने अपने नए कारखाने दूसरी जगहों पर लगाने का काम तेज कर दिया। दूसरी कंपनियां भी इस क्षेत्र में निवेश करने से पहले काफी सोच-विचार करने लगी हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि हरियाणा में रोजगार की कितनी जरूरत है। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। ऐसे में, चुनाव जीतने के लिए यह नारा बुरा नहीं है कि हम प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण दिलवा देंगे और कंपनियों की तसल्ली के बारे में भी सोचा गया होगा। इसीलिए शर्त है कि महीने में 50 हजार रुपये से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में ही आरक्षण देना होगा। एक छूट यह भी दी गई है कि योग्य उम्मीदवार न मिले, तो बाहर के लोगों को रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी हर नियुक्ति के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यानी काम में रोड़ा अटकाने का एक और इंतजाम। कारोबारी इसे इंस्पेक्टर राज की वापसी का सुबूत मान रहे हैं। बीपीओ का तो करीब 80 प्रतिशत स्टाफ इस आरक्षण के दायरे में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर कारोबार के जानकारों से बातचीत में पता चलता है कि ऐसी कंपनियों में 70 प्रतिशत से कुछ ही कम स्टाफ पांच साल से कम अनुभव वाला होता है और इनमें से करीब आधे 50 हजार रुपये से कम तनख्वाह पर काम करते हैं। राहत की बात यह है कि आरक्षण का नियम सिर्फ नई भर्ती के लिए है। कंपनी के मौजूदा स्टाफ पर इसका असर नहीं पड़ना है, लेकिन ये कंपनियां देश भर में साल में लाख-डेढ़ लाख नए लोगों को नौकरियां देती हैं। डर है, अब वे अपना कारोबार गुड़गांव या हरियाणा के बजाय देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की सोचने लगेंगी।

कोरोना काल में जब पूरे-पूरे दफ्तर बंद करके वर्क फ्रॉम होम का अनुभव हो चुका है, तब कंपनियों में यह हौसला भी बढ़ चुका है कि वे आसानी से यहां से वहां जा सकती हैं। लेकिन क्या यह समस्या का हल है? याद कीजिए, वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एलान किया था कि वह ऐसा कानून लाएंगे, जिससे निजी कंपनियों को 70 प्रतिशत नौकरियां राज्य के नौजवानों के लिए आरक्षित करनी होंगी। इसके साल भर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया कि प्रदेश की सारी सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए ही रखने, यानी 100 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाएंगे। इसी किस्म के एलान 1995 में गुजरात और 2016 में कर्नाटक की सरकारें कर चुकी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अमल में नहीं आ सका है। भारत का संविधान राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं देता कि वे इस तरह के आरक्षण लागू करें, जिससे बराबरी के अधिकार का उल्लंघन होता हो। सर्वोच्च न्यायालय भी कई मामलों में यह साफ कर चुका है कि राज्य सरकारें इस तरह भेदभाव करने वाले नियम-कायदे नहीं बना सकतीं। लेकिन कानूनी प्रावधानों में कुछ गुंजाइश भी है और संसद ने जब रोजगार में इस तरह के भेदभाव खत्म करने के लिए कानून पारित किया, तब कुछ राज्यों को रियायत भी दी गई। इसलिए यह आशंका बेबुनियाद नहीं कि दूसरी सरकारें भी ऐसे कानून बनाने की सोचेंगी। हालांकि, यह भी करीब-करीब तय है कि ऐसा कानून अदालत में टिक नहीं पाएगा।

प्रवीण कुमार सिंह

असम-बंगाल विधानसभा चुनाव में विदेशी घुसपैठ, एनआरसी और हिंदू पलायन चुनावी मुद्दे बनने के आसार

> बंगाल की अराजक और हिंसक राजनीति ने राज्य के विकास को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। असुरक्षा और रोजगार के अभाव में भी लोग पलायन को बाध्य हुए हैं। चूंकि असम के साथ बंगाल के भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए विदेशी घुसपैठ और एनआरसी के चुनावी मुद्दा बनने के आसार हैं।
>
> एक तरफ कम्युनिस्ट दल, कांग्रेस और ममता की पार्टी घुसपैठ को नकार रही है तो दूसरी तरफ भाजपा घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की बात कर रही है। चुनाव पूर्व ही तृणमूल और भाजपा के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गए हैं। असम और बंगाल के चुनाव साथ-साथ होने के चलते दोनों राज्यों के चुनावी मुद्दे घुसपैठ तो होने ही चाहिए। इसके साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाए कि हिंदू पलायन का मुद्दा छूटे नहीं।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक 'मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस' में लिखा था, 'भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कश्मीर को लेकर मतभेद है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान से सटे असम और अन्य क्षेत्रों पर भी हमारा दावा बनता है।' पाकिस्तान और उसके शासकों की मंशा को भारत के शासक वोट बैंक के लालच में अनदेखी करते रहे। इसके परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान यानी तत्कालीन बांग्लादेश से एक दीर्घकालिक योजना के तहत भारत में घुसपैठ होती रही। विगत पांच दशकों में देश में मुस्लिम जनसंख्या 3.5 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन असम में यह 11 प्रतिशत तो पश्चिम बंगाल में सात प्रतिशत बढ़ी। जो लोग मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि का बचाव इस रूप में करते हैं कि चूंकि मुस्लिम आम तौर पर परिवार नियोजन नहीं अपनाते अतः उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई दिखती है, वे गलत हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम परिवार नियोजन नहीं अपनाते तो देश के दूसरे राज्यों में भी समान रूप से मुस्लिम जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश से सटे असम-बंगाल और बिहार के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ती गई। ये भारतीय मुसलमानों की संख्या नहीं, बल्कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिये हैं और वे एक साजिश के तहत भारत आ रहे हैं।

1980 में असम के मंगलदोई संसदीय क्षेत्र में जब मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दिखाई पड़ी, तब असम साहित्य परिषद के मार्गदर्शन में घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन चला। बाध्य होकर केंद्र सरकार को असम के लोगों के साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते के बाद भी घुसपैठियों को

निकालने का काम नहीं हो पाया। आज असम के 27 जिलों में से नौ जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण वहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) तो गया, पर अभी भी वह आधा अधूरा है। चूंकि असम जाग गया है इसलिए कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा ही। असम में जब घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो घुसपैठियों ने अपने लिए सबसे सुरक्षित बंगाल को अपनी शरणस्थली बनाया। 1961-71 और 1971-81 में बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 30 प्रतिशत से नीचे थी, जो 1981-91 में अचानक बढ़कर लगभग 37 प्रतिशत हो गई। सवाल यह है कि असम की तरह बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसका एक ही उत्तर है कि बंगाल में सत्ता या विपक्ष में बैठे दल- कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट न केवल घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मान बैठे थे, बल्कि उन्हें संरक्षण भी देते थे। जुलाई 1998 में महाराष्ट्र पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ट्रेन से हावड़ा जा रही थी, ताकि उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके, लेकिन हावड़ा स्टेशन से कुछ पहले ही कम्युनिस्ट नेताओं की अगुआई में हजारों की भीड़ ने उन्हें महाराष्ट्र पुलिस से छुड़ाकर भगा दिया।

विभाजन का दंश झेल चुका बंगाल घुसपैठ की साजिश की कैसी अनदेखी कर रहा है, इसका प्रमाण है इस राज्य का मालदा जिला। विभाजन के बाद 1951 में मालदा में मुस्लिम 36.97 प्रतिशत थे, पर 1961 में वे बढ़कर 46.18 प्रतिशत हो गए। यानी मात्र 10 वर्ष में नौ प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई। आज यह मुस्लिम बहुल जिला है। मालदा की तरह मुर्शिदाबाद भी मुस्लिम बहुल है। पिछली जनगणना में उत्तरी दिनाजपुर भी मुस्लिम बहुल होने के करीब था। अब वह हो भी गया होगा। बंगाल में मुर्शिदाबाद के अलावा कोलकाता, हावड़ा और वीरभूम जिले में भी विगत पांच दशकों में मुस्लिम जनसंख्या आठ से दस प्रतिशत बढ़ी है।

बंगाल के 341 सबडिवीजन में से 66 मुस्लिम बहुल हैं। 2001 में यह संख्या 59 थी। यानी एक दशक में सात मुस्लिम बहुल सबडिवीजन बढ़े। विगत जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि एक दशक में प्रदेश के 341 सबडिवीजन में से 148 में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में दो से पांच गुना है। विगत जनगणना में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम एक प्रतिशत के करीब बढ़े, पर बंगाल के 24 सबडिवीजन में ये तीन से पांच प्रतिशत तक बढ़े। इन 24 में से 11 सबडिवीजन केवल दक्षिण 24 परगना जिले के हैं। राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर दो गुना थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल को पुनः विभाजन झेलना पड़ सकता है। कश्मीर घाटी की तरह बंगाल से भी हिंदुओं का पलायन हो रहा है।

शहरीकरण के इस दौर में कोलकाता में विगत जनगणना में हिंदू जनसंख्या बढ़ने के बदले एक लाख 12 हजार घटी। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर भले 17 प्रतिशत से ऊपर रही हो, पर बंगाल में यह 10 प्रतिशत के करीब थी। राज्य के 27 सबडिवीजन में तो यह सात प्रतिशत से भी कम थी। अगर राष्ट्रीय स्तर पर हुए हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर को आधार माना जाए तो राज्य में 35 लाख से अधिक हिंदुओं का पलायन हुआ है। बंगाल की अराजक और हिंसक राजनीति ने राज्य के विकास को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। असुरक्षा और रोजगार के अभाव में भी लोग पलायन को बाध्य हुए हैं। चूंकि असम के साथ बंगाल के भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए विदेशी घुसपैठ और एनआरसी के चुनावी मुद्दा बनने के आसार हैं।

एक तरफ कम्युनिस्ट दल, कांग्रेस और ममता की पार्टी घुसपैठ को नकार रही है तो दूसरी तरफ भाजपा घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की बात कर रही है। चुनाव पूर्व ही तृणमूल और भाजपा के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गए हैं। असम और बंगाल के चुनाव साथ-साथ होने के चलते दोनों राज्यों के चुनावी मुद्दे घुसपैठ तो होने ही चाहिए। इसके साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाए कि हिंदू पलायन का मुद्दा छूटे नहीं।

सेक्युलरिज्म के ढोंग का सटीक उदाहरण हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाने वाले सिद्दीकी

किसी कांटेदार झाड़ का नाम बरगद रख देने से वह बरगद नहीं हो जाता, लेकिन राजनीति में इसी तरह के काम किए जाते हैं। हैरत यह है कि कुछ लोग ऐसा प्रचारित करने के लिए आगे भी आ जाते हैं कि हां जी, वह झाड़ ही बरगद है। पश्चिम बंगाल में यह तबसे देखने को मिल रहा है, जबसे हुगली स्थित फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नामक राजनीतिक दल का गठन किया है। सबसे पहले अब्बास सिद्दीकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने डोरे डाले। वही ओवैसी जो मीडिया के एक हिस्से और खासकर अंग्रेजी मीडिया की नजर में सेक्युलर लीडर हैं। हालांकि उनके दल का नाम ही मजहबी तेवर वाला यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, फिर भी वह अपने सीने पर सेक्युलर होने का तमगा लगाए घूमते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह देश के उन्हीं इलाकों से चुनाव लड़ते हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक होती है। किसी कारण उनकी अब्बास सिद्दीकी से बात नहीं बनी। माना जाता है कि इसके बाद अब्बास सिद्दीकी को अपने पाले में लाने की कोशिश ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी की, लेकिन ज्यादा सीटें मांगने के कारण बात नहीं बनी। एक समय अब्बास सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस के खास हुआ करते थे। पता नहीं क्यों वह खास से आम हो गए, लेकिन यह सबको पता है कि खुद को सबसे अव्वल दर्जे का सेक्युलर कहने वाले वाम दलों से उनकी बात बन गई। चूंकि कांग्रेस ने बंगाल में पहले ही वाम दलों से मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने भी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से हाथ मिला लिया। अब इसे लेकर कांग्रेस में रार छिड़ी है। कांग्रेस का एक गुट इंडियन सेक्युलर फ्रंट को सेक्युलर मानने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो इस पर मुहर लगा चुका है और उसे चुनौती देने का कोई मतलब नहीं। यह सनद रहे कि एक समय आंध्र प्रदेश में मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस एक साथ ही थे। मजलिस ने 2012 में हैदराबाद में चारमीनार के निकट एक मंदिर के जीर्णोद्धार से खफा होकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था।

यह भी सनद रहे कि केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ का ही एक घटक है और राहुल गांधी जिस वायनाड से लोकसभा चुनाव जीते, वहां मुस्लिम लीग का अच्छा-खासा दखल है। यह जिन्ना की उसी मुस्लिम लीग का अवशेष है, जिसने देश का विभाजन कराया था। विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो नेता भारत में रह गए, उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से अपनी नई राजनीतिक दुकान खोल ली और खुद को सेक्युलर बताने लगे। कांग्रेस ने इस पर भरोसा कर लिया। यह भरोसा आज तक कायम है।

केरल के वामपंथी दल मुस्लिम लीग को सेक्युलर नहीं मानते, लेकिन किसी को कोई मुगालता पालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह तो पहले से ही जगजाहिर है कि केरल में जो कांग्रेस वाम दलों के खिलाफ खड़ी है, वही बंगाल में उनके साथ है। हां तो बात हो रही थी अब्बास सिद्दीकी की। इन दिनों वह सेक्युलरिज्म का गाना खूब जोर से गाते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनका सेक्युलर फ्रंट मुसलमानों के साथ दलितों और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगा। क्या किसी दरगाह का मौलाना ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या वह सेक्युलर नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है, लेकिन तब नहीं जब वह किसी मुस्लिम के मंदिर चले जाने पर उसे काफिर और कौम का गद्दार करार दे। अब्बास सिद्दीकी ऐसा ही कर चुके हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को बेहया करार देते हुए उन्हें पेड़ से बांधकर पीटने की बात कही। उनका 'गुनाह' यह था कि वह एक मंदिर चली गई थीं।अब्बास ने इसी तरह कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम को भी कौम का गद्दार करार दिया, क्योंकि शिवरात्रि पर वह किसी मंदिर चले गए थे।

क्या मौलाना से नेता का चोला धारण करने के बाद उनके विचार बदल गए हैं? नहीं-बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि आखिर मंदिर जाने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? अब्बास सिद्दीकी की सलाह है कि चाहे नुसरत जहां हों या फरहाद हाकिम, इन दोनों को खुलकर कहना चाहिए कि वे मुसलमान नहीं हैं। चर्चित लेखिका तसलीमा नसरीन की मानें तो अब्बास ने फ्रांस के शिक्षक सैम्युल पैटी के कत्ल का समर्थन किया था और वह शरिया कानून के भी हामी हैं। पता नहीं, यह कितना सच है, लेकिन इन दिनों वह वीडियो वायरल है, जिसमें अब्बास सिद्दीकी यह कहते देखे-सुने जा सकते हैं कि अल्लाह कोई ऐसा वायरस भेजे कि हिंदुस्तान में 10-20-50 करोड़ लोग मारे जाएं। अब्बास के मुताबिक यह वीडियो उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कोई घोर मजहबी और सांप्रदायिक शख्स सेक्युलरिज्म की आड़ लेकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा हो। यह काम न जाने कब से हो रहा है और इसी कारण इस देश में सेक्युलरिज्म एक हेय शब्द बन गया है। सेक्युलरिज्म किस तरह ढोंग और छल-कपट का पर्याय बन चुका है, इसका ताजा और सटीक उदाहरण हैं अब्बास सिद्दीकी। वह सांप्रदायिक राजनीति भी कर रहे और ठसक के साथ अपने दल को इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी कह रहे हैं।

कारोबार की नेता स्त्रियां

जानी-मानी अकाउंटिंग फर्म ग्रैंट थॉर्नटन की ओर से बिजनेस लीडरशिप के मामले में महिलाओं की स्थिति पर जारी की गई ताजा सालाना रिपोर्ट पहली नजर में जरूर राहत देने वाली है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को लीडरशिप रोल देने के मामले में भारतीय उद्योग जगत फिलिपींस और साउथ अफ्रीका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। यहां सीनियर मैनेजमेंट में महिलाओं का प्रतिशत 39 है जो वैश्विक औसत (31 फीसदी) से कहीं अधिक है। निश्चित रूप से यह तथ्य भारतीय कॉरपोरेट जगत की अच्छी तस्वीर पेश करता है, हालांकि यह बदलाव हाल के वर्षों की देन है। ग्रैंट थॉर्नटन की ही 2015 की सर्वे रिपोर्ट में इस पहलू से भारत की स्थिति खासी कमजोर नजर आती है। उस साल बिजनेस लीडरशिप रोल में महिलाओं का प्रतिशत हमारे यहां महज 15 दर्ज किया गया था और सूची में भारत को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया था। 14 फीसदी के साथ जर्मनी और 8 फीसदी के साथ जापान ही उससे नीचे थे। अगर इन पांच वर्षों में बिजनेस जगत में महिलाओं की स्थिति में ऐसा जबर्दस्त अंतर आया है तो यह यूं ही नहीं हो गया होगा। इसके पीछे सोचे-समझे प्रयासों की बड़ी भूमिका है।

हालांकि यह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में महिलाओं को शामिल करने जैसा औपचारिक मामला नहीं है। सीईओ, एमडी, सीओओ और सीएफओ जैसे महत्वपूर्ण पद कोरी प्रतिष्ठा की चीज नहीं हैं। इन पर बैठे व्यक्ति की योग्यता से कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित होता है। बावजूद इसके, कॉरपोरेट जगत में महिलाओं की बेहतर स्थिति को अगर हम भारतीय समाज में महिलाओं की हकीकत से जोड़ लेंगे तो गलती करेंगे। समाज की तो छोड़िए, देश के कुल वेतनभोगी कार्यबल में भी महिलाओं की स्थिति पर नजर डाली जाए तो वह दिनोंदिन पहले से कमजोर ही होती नजर आ रही है। भारतीय थिंक टैंक सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी) की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी (यूएफएलपी) 2019-20 में मात्र 9.7 फीसदी थी, जो अप्रैल 2020 में और कम 7.35 फीसदी दर्ज की गई जबकि नवंबर 2020 तक आते-आते यह उससे भी घटकर 6.9 फीसदी हो गई।

इसका मतलब साफ है कि लॉकडाउन का खामियाजा महिला कर्मचारियों को पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा भुगतना पड़ा है। इससे कंपनी प्रबंधन की नजर में महिला कर्मचारियों की हैसियत का अंदाजा मिलता है।

समाज में एक इंसान के रूप में भी महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की जो शुरुआत संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाए जाने और फिर 2012 के निर्भया कांड की प्रतिक्रिया में उभरे जनांदोलनों से हुई थी, वह प्रक्रिया भी इधर तेजी से पीछे छूटती नजर आ रही है।

यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लिया जाए या उनपर शासन तथा समाज की प्रतिक्रिया को या फिर न्यायपालिका से आने वाले फैसलों को, हर स्तर पर चीजें स्त्री हितों के खिलाफ ही जा रही हैं। ऐसे में बिजनेस लीडरशिप रोल से जुड़े इन आंकड़ों पर बहुत ज्यादा खुश होने की गुंजाइश नहीं है।

सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही सामग्री पर अंकुश के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

> इसका नतीजा यह था कि कई प्लेटफॉर्म पर तो बेहद अश्लील सीरीज भी परोसे जा रहे थे, बिना किसी वर्गीकरण के। कहीं किसी कोने में छोटा सा 18 प्लस लिख दिया जाता था, लेकिन किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं थी। कोई भी उसको देख सकता था। जहां तक कलात्मक स्वतंत्रता बाधित करने की बात है तो उसको लेकर जो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि हमारे देश में फिल्मों को भी रिलीज करने के पहले प्रमाणन करवाना होता है। क्या इस प्रमाणन की व्यवस्था से फिल्मों की कलात्मक स्वतंत्रता बाधित हुई टीवी चैनलों को लेकर स्वनियमन लागू है, तो क्या टीवी पर दिखाई जानेवाली सामग्रियों में कलात्मक स्वतंत्रता बाधित दिखती है दरअसल इस तरह के नियमनों से अराजकता पर रोक लगती है।

हाल के दिनों में दो-तीन ऐसी खबरें आईं जो मनोरंजन की दुनिया की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। एक खबर है कि अमेजन प्राइम वीडियो से जुड़ीं अपर्णा पुरोहित का उत्तर प्रदेश पुलिस ने बयान दर्ज करवाया। ये बयान वेब सीरीज तांडव में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दर्ज कराए गए केस के संबंध में लिया गया है। अपर्णा से लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में पुलिस ने पूछताछ की। इससे जुड़ी एक और खबर आई प्रयागराज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। अपर्णा पर वेब सीरीज तांडव को लेकर नोएडा में भी केस दर्ज हुआ था, उस सिलसिले में वह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत चाहती थीं।

पिछले कई वर्षो से वीडियो स्ट्रीमिंग साइट, जिसे ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, पर दिखाई जाने वाले वेब सीरीज की सामग्री को लेकर तो कई बार वहां दिखाई जाने वाली फिल्मों को लेकर विवाद होते रहे हैं। पिछले तीन वर्षो से इन वेब सीरीज पर दिखाई जाने वाली सामग्री में हिंसा, यौनाचार और मनोरंजन की आड़ में विचारधारा की पैरोकारी, हिंदू धर्म प्रतीकों के गलत चित्रण से लेकर अन्य कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। जब भी इन बातों को लेकर विवाद उठते थे तो सरकार से ये मांग भी की जाती थी कि ओटीटी पर दिखाई जाने वाली सामग्री के संदर्भ में विनियमन नीति लागू की जानी चाहिए। इस स्तंभ में भी लगातार इस बारे में चर्चा की जाती रही है कि इस क्षेत्र में बढ़ रही अराजकता पर अंकुश लगाने के

लिए सरकार को दिशा-निर्देश या कंटेंट के प्रमाणन की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के स्तर पर विनियमन लागू करने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर के संवाद भी हुए थे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर 2018 में सख्त टिप्पणी की थी, संसद में भी यह मामला कई बार उठा। सरकार ने इस पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश में ओटीटी पर दिखाई जाने वाली सामग्री के लिए स्वनियमन की बात की गई है, लेकिन ये नियमन कैसे हो और इसका दायरा क्या हो इसको भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को आघात पहुंचाने वाले दृश्य और संवाद नहीं दिखाएंगे। कलात्मक स्वतंत्रता की आड़ में कोई भी ऐसी सामग्री दिखाने की अनुमति नहीं होगी जो कानून सम्मत नहीं है। लेकिन सरकार ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए सेवा प्रदाताओं को इसका तंत्र विकसित करने को कहा है।

अच्छी बात ये है कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें कार्यक्रमों को दिखाने के पहले किसी से अनुमति लेने की बात नहीं है यानी प्री सेंसरशिप का रास्ता सरकार ने नहीं अपनाया। सबकुछ इन प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया है। सेवा प्रदाता कंपनियों को खुद अपनी सामग्रियों का वर्गीकरण करना होगा।

अलग अलग उम्र की मनोरंजन सामग्रियों का वर्गीकरण कर दिया गया है। सेवा प्रदाताओं को इसका पालन करना होगा। अगर किसी को शिकायत होती है या किसी प्रकार से इन नियमों का उल्लंघन होता है तो उससे निबटने के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। ये व्यवस्था लगभग उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर टीवी के कार्यक्रमों का स्वनियमन होता है। सरकार के इस स्वनियमन के दिशा-निर्देशों को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ स्वयंभू निर्देशक इसे कलात्मक स्वतंत्रता को बाधित करनेवाला कदम बता रहे हैं। दरअसल जब वो कलात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं को भी स्पष्ट किया गया है। ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले इन मनोरंजन के माध्यमों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। कई देशों में ओटीटी के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं। सिंगापुर में तो इसके लिए एक प्राधिकरण है- इंफोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना ब्रॉडकास्टिंग एक्ट के तहत की गई थी। इसमें सभी सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडकास्टिंग एक्ट के अंतर्गत इस प्राधिकरण से लाइसेंस लेना पड़ता है।

ओटीटी, वीडियो ऑन डिमांड और विशेष सेवाओं के लिए एक विशेष कंटेंट कोड है। इसमें सामग्रियों के वर्गीकरण की व्यवस्था है। सिंगापुर की संबंधित अथॉरिटी को अधिकार है कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जानेवाली सामग्री को अगर कानून सम्मत नहीं पाती है तो उसका प्रसारण रोक दे। नियम विरुद्ध सामग्री दिखाने पर जुर्माना लगाने का भी प्रविधान है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के लिए ई-सेफ्टी कमिश्नर हैं। उनका दायित्व है कि वे डिजिटल मीडिया पर चलनेवाली सामग्रियों पर नजर रखें। वहां विनियमन इस हद तक है कि ई-सेफ्टी कमिश्नर अगर पाते हैं कि किसी मनोरंजन सामग्री का वर्गीकरण अनुचित है या गलत तरीके से किया गया है तो वो दंड के तौर पर उसे प्रतिबंधित भी कर सकते हैं।

यहां भी ओटीटी पर चलनेवाली सामग्री की शिकायत मिलने पर उसके निस्तारण की एक तय प्रक्रिया है। इसके अलावा भी दुनिया के अन्य कई देशों में किसी न किसी तरह के दिशा-निर्देश लागू हैं। हमारे देश में अब तक ओटीटी की सामग्री को लेकर किसी तरह का नियमन नहीं था। इसका नतीजा यह था कि कई प्लेटफॉर्म पर तो बेहद अश्लील सीरीज भी परोसे जा रहे थे, बिना किसी वर्गीकरण के। कहीं किसी कोने में छोटा सा 18 प्लस लिख दिया जाता था, लेकिन किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं थी। कोई भी उसको देख सकता था। जहां तक कलात्मक स्वतंत्रता बाधित करने की बात है तो उसको लेकर जो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि हमारे देश में फिल्मों को भी रिलीज करने के पहले प्रमाणन करवाना होता है। क्या इस प्रमाणन की व्यवस्था से फिल्मों की कलात्मक स्वतंत्रता बाधित हुई टीवी चैनलों को लेकर स्वनियमन लागू है, तो क्या टीवी पर दिखाई जानेवाली सामग्रियों में कलात्मक स्वतंत्रता बाधित दिखती है दरअसल इस तरह के नियमनों से अराजकता पर रोक लगती है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

इंदौरः पुलिस पेट्रोल पंप पर घूरने के विवाद में गोली चली

इंदौर। 15वीं बटालियन के सामने स्कूटर पर आए दो युवक और युवती का कर्मचारियों से विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक ने हवाई फायर कर दिया। मौजूद कर्मचारी ने पत्थर बरसाकर जान बचाई । अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। योगेश ने पुलिस को बताया कि वह महेश गार्ड लाइन स्थित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। छह मार्च को रात करीब 11.30 बजे स्कूटर पर दो युवक और एक युवती पेट्रोल लेने के लिए आए थे। जब उन्हें पंप बंद होने का हवाला दिया, युवक गरमी दिखाने लगा। इसी दौरान एक युवक ने कहा घूर कर क्यों देख रहा है। वह कुछ समझ पाता। इसके पहले बीच में बैठा युवक उतरा और कट्टे से फायर कर दिया।

रीवाः छात्रा ने पुल से नदी में लगाई छलांग, सुरक्षित बचाया

रीवा। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक छात्रा पुल से नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घर से स्कूल के लिए निकली 11 वीं की छात्रा ने सुबह छोटी पुल से बीहर नदी में छलांग लगा दी, जिसे वहां नहा रहे कुछ युवकों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा किसी बात को लेकर घर वालों से परेशान थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। पुलिस छात्रा को पूछताछ के लिए थाने ले आई। छात्रा ने अपने भाई पर मोबाइल पर बात करने को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद सामने आया है।

भोपालः हरदा का घायल बाघ स्वस्थ, वापस जंगल भेजा

भोपाल। भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान उपचार बाद बाघ को मंगलवार को पूर्णतः स्वस्थ कराकर अपने प्राकृतिक रहवास को प्रस्थान करा दिया गया है। संचालक वन विहार अजय यादव ने बताया कि बाघ को घायल अवस्था में हरदा से रेस्क्यू कर 13 जनवरी को यहां लाया गया था। बाघ तत्समय मरणासन्न अवस्था में था। इसके सिर पर गंभीर घाव थे और सिर और उसके पैर में फ्रैक्चर था। वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. अतुल गुप्ता और सहयोगी स्टाफ के प्रयासों का नतीजा यह निकला कि घायल बाघ को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया गया। वन मंत्री विजय शाह एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक ने इस बाघ का बाह्य निरीक्षण किया और चिकित्सकों की सलाह पर इसे प्राकृतिक रहवास में छोड़े जाने की सहमति दी।

उज्जैनः शिप्रा में बहे युवक का शव बरामद

उज्जैन। सोमवार 8 मार्च को शक्करवासा स्थित नर्मदा लिंक परियोजना स्थल पर शेखर ठाकुर पिता अजय ठाकुर उम्र 18 वर्ष द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में स्नान किया जा रहा था। नर्मदा से प्रवाहित जल का बहाव तेज होने के कारण शेखर शिप्रा के पानी में डूब गया। होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की संयुक्त टीम के द्वारा पिछले 20 से अधिक घंटे तक सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसमें मुख्यतः प्रशिक्षित जवानों के द्वारा तैराकी एवं गोताखोरी तथा बिलाई की मदद से बॉडी को खोजने का प्रयास किया गया। शिप्रा की तलहटी में कीचड़ एवं मछली पकड़ने के जाल होने के कारण रेस्क्यू कार्य में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही थी।

रायपुरः छग विधानसभा सत्र 17 दिन पहले ही समाप्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 17 दिन पहले ही मंगलवार को समाप्त हो गया। इसके साथ की विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र 22 फरवरी को शुरू हुआ था,और इसे 26 मार्च तक चलना था। बजट के बाद विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा में कतिपय गतिरोध के चलते मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हिस्सा नहीं लिया जिसके चलते एक-एक दिन में दो तीन विभागों की अनुदान मांगों को मंजूरी मिल गई। सदन में कल ही विभागों की अनुदान मांगो की चर्चा पूरी हो गई थीं, मंगलवार को विनियोग विधेयक की मंजूरी के साथ ही सत्रावसान हो गया।

रसिन बांध के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री बोले- जो कहते हैं मोदी-योगी ने क्या किया, अब उन्हें जवाब दें किसान

बांदा । महोबा के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंच गए। यहां पर उन्होंने रसिन बांध का लोकार्पण करने के बाद सेल्फी भी ली। इसके बाद मंच पर पहुंचते ही जनता ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया तो मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने वालों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि किसानों को गुमराह वे लोग कर रहे हैं, जिन्हें उनके चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती है। आज दुनिया को भारत की ताकत पर भरोसा है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री के कार्यों को सम्मान मिलता है। जो लोग कहते हैं कि मोदी योगी ने किसानों के लिए क्या किया, उन्हें जवाब दें कि जो काम आजादी बाद नहीं हुए उन्हें हमने करा। रसिन बांध, अर्जुन सहायक व चिल्लीमल पंप कैनाल जैसी परियोजना 1970 में बनी थी लेकिन वर्षों से लंबित थी। इन्हें हमारी सरकार ने पूरा किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर चित्रकूट बने ये हमारी प्राथमिकता है, किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं, वह बताएं किसानों के लिए क्या किया। रसिन बांध और चिल्लीमल परियोजना को अन्य सरकारें जानबूझकर सफल नहीं होने दे रही थीं, योजनाओं को सफल करने के लिए पैसा ही नहीं दिया। विपक्षी दल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे चिल्लीमल और रसिन बांध आदि परियोजना विकास का आधार बनेंगी। वर्ष 2022 तक हर परिवार को एक-एक घर देंगे। बुंदेलखंड से पलायन करने वाले मजदूरों और विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले उनके युवा बेटों के परिवारों का प्रदेश सरकार दो लाख रुपये का जीवन बीमा और पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा करेगी।

सुबह करीब 11 बजे चित्रकूट के चौधरी चरण सिंह रसिन बांध सिंचाई परियोजना स्थल पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां पर प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, लोक निर्माण राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद आरके सिंह पटेल, मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा चंद्र प्रकाश खरे, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला व एसपी अंकित मित्तल ने मुख्यमंत्री का फूल माला से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पास ही पार्क में शिव मंदिर में पहुंचे, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंडितों ने पूजा अर्चन कराया और फिर मुख्यमंत्री ने 140.20 करोड़ लागत से बने रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से क्षेत्र के 17 गांवों में 3635 किसानों को 2290 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मंच से ही मुख्यमंत्री ने राजापुर तहसील में यमुना नदी पर 50.46 करोड़ की लागत से बने चिल्लीमल पंप हाउस का वर्चुअल लोकार्पण किया तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट के गूंज उठा। इस परियोजना से 4450 किसानों को 7778 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई के लिए अब साल भर पानी मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में लहचुरा बांध और अर्जुन सहायक परियोजना के रेगुलेटर को देखने के बाद सभा में कहा कि भाजपा सरकार में जलशक्ति मंत्रालय ने पानी का पावर दिखा दिया है। दो दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर आए मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह ललितपुर से सीधे महोबा पहुंचे। यहां पहले हेलीकॉप्टर से लहचुरा बांध का जायजा लिया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पर अफसरों और नेताओं ने उनका स्वागत किया।

महोबा के लहचूरा बांध के पास कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर सुबह करीब 9.52 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां गेट नंबर तीन से वह अधिकारियों के साथ मंच पर पहुंचे। सीएम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल का काम चल रहा है, उसमें प्रशासन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। उन्होंने जलशक्ति मंत्रात्रलय के लिए कहा कि अभी तक लोग समझते थे कि जलशक्ति मंत्रालय केवल हैंडपंप ही लगवाता है लेकिन मंत्रालय ने पानी का पावर दिखा दिया है।

सीएम ने कहा, जब से मोदी सरकार आई है, तब से तमाम बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं संचालित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने करीब सात मिनट तक अपने संबोधन में बुंदेलखंड के विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताया। कई परियाजनाएं शुरू करके अबतक असिंचित बुंदेलखंड को सिंचित बनाने को लेकर सरकार के प्रयास का बखान किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए कहा कि वह चुनकर सदन में पहुंचते हैं, जहां बुंदेलखंड के विकास और गरीब किसानों की आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा महोबा वीरों की भूमि है, यहां से मेरा विशेष लगाव रहा है। पिछली बार जब आया था तब यहां से कई बातों को सीखा है। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ अर्जुन सहायक परियोजना के रेगुलेटर, लहचुरा बांध तथा अन्य कार्यों को देखा और अफसरों से पूछताछ की।

इंदौर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी

शिवराज बोले 'ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है और भूमाफिया मध्यप्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं!

इंदौर, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इंदौर में माधव सृष्टि चमेली देवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने माफियाओं को चेतावनी देते हुए प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मैं मध्यप्रदेश को पूरी तरह से माफियाओं से मुक्त कर ही चैन की सांस लूंगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया पर दुनियाभर में ट्रेंड हो रहे पावरी गर्ल के अंदाज में दिखे। उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा, 'ये मैं हूँ! मध्यप्रदेश में मेरी (बीजेपी की) सरकार है! यहां मेरी सशक्त प्रशासनिक टीम है! और भूमाफिया मध्यप्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं!'

उन्होंने आगे कहा कि मैं और मेरी सरकार माफियाओं के सफाये के लिए संकल्पित हैं। अब तक 1000 से अधिक सोसायटियों में जमीनों को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर पात्रों को उनका भू-खंड देने की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर पंचायत सोसायटी और देवी अहिल्याबाई सोसायटी के करीब तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि के 1500 भूखंड मुक्त कराकर पात्र सदस्यों को दिये जा रहे हैं। अगले 4 महीने में 12 सोसायटियों की समस्याओं का समाधान कर 35000-40000 करोड़ के भूखंड पात्र सदस्यों को दिए जाएंगे।

'टाइगर अभी जिंदा है' और शिकार पर निकला है

शिवराज ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर शिकार पर निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का और शिकार मां-बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जनता हमारी भगवान है। उनको न्याय दिलाना हमारा धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और गड़बड़ करने वालों को सजा मिले, यह हमारा संकल्प है।

पटना के नर्सिंग कॉलेज में अपने विदाई समारोह के दौरान शपथ ग्रहण करते हुए नर्सिंग छात्राएं।

टाइगर को आदमखोर घोषित करने के मामले में कोर्ट सख्त

जबलपुर। टाइगर को आदमखोर घोषित कर उसे वन विहार तथा चिड़िया घर में भेजे जाने के खिलाफ दायर मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया। मामले में चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने केंद्र सरकार के वन एव पर्यावरण विभाग, एडीजी फॉरेस्ट व डॉक्टर वाईल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तथा नेशनल टाईगर कंजरवेटर अथॉरिटी को अनावेदक बनाने की अनुमति प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार व एनटीसीए से मांगा जवाब

यह जनहित का मामला दिल्ली निवासी वन्य जीव विशेषज्ञ संगीता डोंगरा की ओर से हाईकोर्ट में दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक टाइगर भटकते हुए सारणी बैतूल भेजा गया था। चंद्रपुर से सारणी तक पहुंचने के दौरान टाइगर ने दो व्यक्ति तथा जानवरों पर हमला किया था। जिसके बाद बाघ को आदमखोर बताते हुए उसे वन विहार भोपाल भेजने के आदेश जारी कर दिये गये थे।

सरकार की ओर से पेश किये गये जबाव में बताया गया था कि उक्त टाइगर ने महाराष्ट्र में भी मानव व हमला किया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका में अनावेदकों की संख्या में बढ़ोतरी किये जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। युगलपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को छोड़कर अन्य संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की है। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा।

लखनऊ विधानभवन के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस पर दुष्कर्म के आरोपी को नहीं पकड़ने का आरोप

लखनऊ । राजधानी में विधानभवन के सामने एक बार फिर आत्मदाह का प्रयास किया गया। बुधवार दोपहर 12 बजे करीब एक महिला ने विधानभवन के गेट नंबर पांच के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बचा लिया।

बताया जा रहा है कि महिला सुलतानपुर की रहने वाली है। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों की सर्तकता की वजह से महिला को आत्मदाह करने से रोका गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपित को पुलिस ने नहीं पकड़ा। जिससे वो काफी क्षुब्ध है। प्रभारी निरीक्षक थाना हुसैनगंज ने बताया कि मंगलवार को बापू भवन के पास सुल्तानपुर निवासी युवती आई थी।

महिला का कहना था कि उसने अपने स्थानीय थाने पर दुष्कर्म का मुकदमा लिखाया था। जिसमें आरोपित राजू पकड़ा गया था और पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया। इससे नाराज होकर उसने बापू भवन के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया था। जिनको पुलिस ने पकड़ लिया। महिला सुरक्षित है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

छात्रों ने कृषि मंत्री के बंगले को घेरा, खून से लिखा पत्र, मांगी इच्छा मृत्यु

ग्वालियर। कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार दोपहर ने केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर हंगामा किया। यही नहीं, छात्रों ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर न्याय मांगा है। छात्रों ने चिट्ठी में लिखा है कि 'न्याय दो या इच्छा मृत्यु'। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

पीईबी द्वारा कृषि छात्रों की 10 और 11 फरवरी को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने के संबंध में छात्रों का प्रदर्शन 18 दिन से चल रहा है। मंगलवार को इसी कड़ी में दोपहर करीब आधा सैकड़ा छात्र एकत्रित होकर हाथों में तख्ती बैनर लेकर रेसकोर्स रोड कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गए। यहां पहुंचकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों को गार्ड ने बताया कि कृषि मंत्री शहर में नहीं हैं। इसके बाद कृषि महाविद्यालय के छात्र नहीं माने और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपने खून से चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है। छात्रों का कहना था, बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। अब तो छात्रों को न्याय दिलाया जाए या इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए।

अनूपपुर में पिकअप के पेड़ से टकराने से तीन की मौत, 24 लोग घायल

अनूपपुर, (आरएनएन)। जिले के करनपठार थाना क्षेत्र के भेसंटोला गांव के एक कार्यक्रम में शामिल होकर डिण्डोरी वापस लौट रही पिकअप पिपरिया गांव के पास एक पेड़ से टकरा गई ,जिससे दो ग्रामीणों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक ने मंगलवार दोपहर अस्पताल में दमतोड़ दिया।

सतना में बस पलटी, दो की मौत, 36 लोग घायल

सतना। रीवा से नागपुर जा रही इस बस में सवार दो लोगों की मौत हो गई जिसमें यूपी के कौशांबी जिले के निवासी यात्री छोटेलाल पंचम भी रहे। इस हादसे में 36 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सतना के अमदरा के पास रैगवा में एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मां शारदा ट्रेवल्स की गोल्डन क्वीन बस रीवा के हनुमना से नागपुर जा रही थी। अमदरा थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश दुबे ने बताया कि एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि दूसरे यात्री ने मैहर में दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाइवे पर बस जैसे ही रैगवा के पास पहुंची, एक बाइक सामने आ गई। बस ड्राइवर ने उसे बचाने की कोशिश की तो चालक स्टेयरिंग पर से नियंत्रण खो बैठा और बस बेकाबू हो कर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर चलती बस से कूद गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार रात भेसंटोला गांव के समीप हुई इस दुर्घटना में जीतेन्द्र नन्दा (23) और गेंदलाल नन्दा (60) की मौके पर मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में 24 लोग घायल हुए ,जिसमें12 गंभीर घायल हुए थे। मंगलवार दोपहर अनूपपुर जिला अस्पताल में ओमती बाई ढीमर (28) की मौत हो गई।

इंदौर के निजी बैंक में कार्यरत महिला सहायक बैंक मैनेजर की हत्या

खरगोन, (एजेंसी)। जिले के बड़वाह थाना क्षेत्र में इंदौर के एक निजी बैंक में कार्यरत महिला सहायक ब्रांच मैनेजर हत्या कर दी गयी है। बड़वाह के नगर निरीक्षक संजय द्विवेदी ने बताया कि सोमवार को नाव घाट खेड़ी के एक्वाडक्ट पुल के पास संगम रोड की झाड़ियों में एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिला था। उसके लॉकेट के पेंडल में क्वीन लिखे होने की सूचना सोशल मीडिया पर प्रचारित किये जाने पर उसकी शिनाख्त हो गयी थी, जो मूलतः खंडवा की निवासी थी और पिछले 3 वर्षों से इंदौर के एक निजी बैंक में कार्यरत थी।

झाड़ियों में नग्न अवस्था में मिला शव

श्री द्विवेदी ने बताया कि वह 5 मार्च को अपने दुपहिया वाहन से इंदौर स्थित घर से निकली थी और लापता हो गई थी। उन्होंने बताया कि मृतक महिला का मोबाइल फोन तथा दुपहिया वाहन भी नहीं मिला है। उन्होंने महिला के सिर पर पाए गए चोट के निशान व अन्य तथ्यों के आधार पर बताया कि उसकी हत्या हुई है। उन्होंने बताया कि लाश 3 दिन पुरानी होने के चलते महिला के साथ दुष्कर्म होने सम्बन्धी जानकारी अन्य परीक्षणों से ही पता चल सका है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है।

शराब की बोतल गले में लटकाकर जनसुनवाई में पहुंच गया पूर्व पार्षद

वार्ड में अवैध शराब ब्रिकी से है परेशान

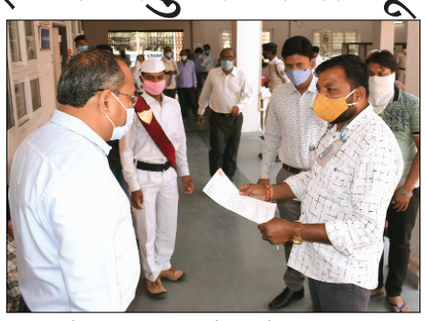

होशंगाबाद , (एजेंसी)। मंगलवार को एक पूर्व पार्षद गले में शराब की खाली बोतलें लटकाकर जनसुनवाई में पहुंच गया। पूर्व पार्षद अपने वार्ड में बिक रही अवैध शराब और मीट कारोबार का विरोध कर रहा है। शराब बोतल की माला पहने पूर्व पार्षद कलेक्टर के पास पहुंच गया। वहां से उसे आवेदन पंजीकृत कराने भेजा गया।

दसअसल नारायण नगर क्षेत्र में पुलिया के पास अवैध शराब का कारोबार जमकर चल रहा है। शाम होने के बाद यहां आपराधिक गतिविधियां शुरू हो जाती है। हालत यह है कि राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। पीड़ित लोगों ने इसकी जानकारी आबकारी विभाग को दी, लेकिन शराब का कारोबार करने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की परेशानी को देखते हुए वार्ड 18 के पूर्व पार्षद प्रवीण यादव ने शराब की बोतलों की माला गले में लटकाकर जनसुनवाई में विरोध प्रदर्शन किया। यादव कलेक्टर के पास पहुंच गए। इसके बाद उनका आवेदन कार्रवाई के लिए भेजा गया।

जनसुनवाई में आए लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक युवक शराब की बोतलों की माला पहनकर खड़ा हो गया। मौजूदा लोगों ने जब युवक से बात की तो पूर्व पार्षद यादव ने बताया कि नारायण नगर की पुलिया पर शराब का कारोबार हो रहा है। यहां अवैध रूप से मीट की दुकान भी लगाई जाती है। इससे आमजन परेशान हैं।

महामारी — राज्य में अब तक 3874 मरीज गवां चुके अपनी जान

प्रदेश में कोरोना के 457 नए मामले, दो की मौत

तेजी से बढ़ रही सक्रिय मरीजों की संख्या

भोपाल, (एजेंसी)।

प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मंगलवार को 457 नए मरीज मिले तथा दो मरीजों की इस बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो बढ़कर अब 3711 तक पहुंच गया है।

राज्य स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा रात्रि को जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में कोरोना के 14,886 नए सैंपल जांचे गए, जिनमें 457 मरीजों की रिपोर्ट पॉजीटिव आईं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़ गई। यह मंगलवार को तीन प्रतिशत रही। इसके अलावा दो नए मरीजों की मृत्यु हो जाने के बाद प्रदेश भर में अब तक 3874 मरीज अपनी जान गवां चुके हैं।

प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में इजाफा होने के चलते एक्टिव (उपचारत) मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां संख्या 3711 तक पहुंच गई है। वहीं, राहत की बात यह रही कि 382 नए मरीज स्वस्थ हो गए, जिसके बाद प्रदेश में अब तक 2,57,942 मरीज कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में सबसे अधिक 157 नए मामले इंदौर में सामने आए। वहीं, राजधानी भोपाल में 86 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गई है। इन दोनों शहरों के अलावा जबलपुर में 28, ग्वालियर में 16, उज्जैन में 16, खरगोन में 15, सागर में 12, छिंदवाड़ा में 15, बुरहानपुर में 10, मंदसौर में 8, रीवा में 8, रतलाम 7 सहित अन्य जिलों में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं।

इंदौर में कोविड से डॉ. मुकेश जैन की मौत, शिवराज ने जताया शोक

इंदौर। आगर मालवा जिला अस्पताल में पदस्थ कोरोना वारियर्स योद्धा डॉ. मुकेश जैन का चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया है। कुछ दिनों पहले उन्हें इंदौर चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया था। सोमवार रात 10.20 बजे उनका एमजीएम चेन्नई अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉ. जैन के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया है।

डॉ. जैन आगर-मालवा जिला अस्पताल में पैथोलाजिस्ट के पद पर पदस्थ थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने उनके इलाज के लिए चेन्नई से डॉक्टरों की टीम बुलवाई थी। हालांकि इंदौर में चल रहे इलाज के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस कारण उन्हें सरकार की मदद से इंदौर से एयरलिफ्ट कर चेन्नई शिफ्ट किया गया था। डॉ. जैन के निधन पर इंदौर के आईएमए सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए शोक जताया और कहा कि आगर मालवा जिला अस्पताल में तैनात कोरोना वॉरियर डॉक्टर मुकेश जैन जी को लाख कोशिशों के बाद भी हम बचा न सके। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति दें। वे सदैव एक स्वास्थ्य योद्धा के रूप में हमारे दिलों में रहेंगे।

मुंबई में भारतीय नौसेना में पी -75 आईएनएस करंज पनडुब्बी के कमीशन समारोह के दौरान भारतीय नौसेना के अधिकारी।

अनुच्छेद 370 रद होने के बाद जम्मू-कश्मीर में कम हुई आतंकी हिंसा, 2020 में मारे गए इतने आतंकवादी

नई दिल्ली, एजेंसी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 रद किए जाने के बाद से जम्मू--कश्मीर में आतंकी हिंसा में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। सरकार ने 2019 की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश में 2020 में आतंकी घटनाओं में कमी आने का उदाहरण दिया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में अलगाववादियों, ओवर ग्राउंड कार्यकर्ताओं, पथराव करने वालों समेत करीब 173 लोग अभी तक हिरासत में हैं। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि पाकिस्तान की शह पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले 42 संगठनों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे आतंकी संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद शामिल हैं।

एक लिखित उत्तर में रेड्डी ने कहा कि 2020 में जम्मू एवं कश्मीर में 244 आतंकी घटनाएं हुई। इससे पहले 2019 में 594 ऐसी घटनाएं हुई थीं। 2020 में 221 आतंकी ढेर किए गए जबकि एक साल पहले 2019 में 157 आतंकी मारे गए थे। उन्होंने कहा कि 2020 में 33 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और छह नागरिकों की मौत हुई थी जबकि 2019 में 27 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और पांच नागरिकों की जान गई। केंद्र शासित प्रदेश में इस साल फरवरी में 15 आतंकी घटनाएं हुई जिसमें आठ आतंकी मारे गए।

एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने बताया, एक अगस्त, 2019 के बाद से कई अलगाववादियों, पथराव करने वालों समेत 627 लोगों को अलग--अलग समय पर हिरासत में लिया गया था। नियमित समीक्षा एवं वास्तविक स्थिति के आधार पर इनमें से 454 लोग अभी तक रिहा किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में जन सुरक्षा कानून के तहत अब कोई भी नजरबंद नहीं है।

230 लोगों को मिली है वीआइपी सुरक्षा- एक सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह रायमंत्री रेड्डी ने कहा कि देश में 230 लोगों को सीआरपीएफ और सीआइएसएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा जेड प्लस, जेड और वाई श्रेणियों के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के आकलन के आधार पर सुरक्षा दी जाती है और इसकी समय--समय पर समीक्षा की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा कवर जारी रखने, वापस लेने या संशोधित करने का फैसला होता है।

कलेक्टर ने की गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा

जबलपुर (एजेंसी)। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन की चल रही तैयारियों की आयोजित बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश बाथम तथा उपार्जन व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में खरीदी केन्द्रों का शीघ्र निर्धारण करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि केन्द्रों का निर्धारण करने किसानों की सुविधा के मुताबिक ही किया जाये। उन्होंने गेंहू के उपार्जन के लिए गोदाम स्तर पर खरीदी केन्द्रों के निर्धारण को प्राथमिकता देने तथा ज्यादा से ज्यादा महिला स्व.सहायता समूहों को खरीदी केन्द्रों की जिम्मेदारी देने की बात कही।

खरीदी केन्द्रों के निर्धारण में किसानों की सुविधा का ध्यान रखने दिए निर्देश

कलेक्टर ने बैठक में समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन के लिए भी खरीदी केन्द्रों का शीघ्र निर्धारण करने के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा ने खरीदी केन्द्रों की मेपिंग में भी किसानों की सहूलियतों का विशेष ध्यान देने पर जोर दिया ताकि किसानों को उपज को लेकर %यादा दूरी तय न करनी पड़े। उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत अधिकारियों को दी साथ ही भंडारण एवं परिवहन के समुचित इंतजाम भी करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि रा%य शासन के निर्देशानुसार जिले में 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। चना उपार्जन के लिए आठ खरीदी केन्द्र बनाये जा रहे हैं। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन एक अप्रैल से प्रारंभ किया जायेगा।

कामगार यूनियन ने जताया रोष, की मांग

जबलपुर (एजेंसी)। कामगार यूनियन ने आयुध निर्माणी खमरिया प्रशासन को पत्र लिखकर पुनः स्पष्ट किया है कि निर्माणी दिवस पर ट्रेक सूट या रिस्ट वॉच का यूनियन ने जो प्रस्ताव दिया है, उससे कम का गिफ्ट यूनियन को स्वीकार नहीं होगा। उल्लखनीय है कि गत दिवस सभी यूनियन एसोसिएशन की आयोजित बैठक में निर्माणी दिवस के अवसर पर कामगर यूनियन ने ट्रेक सूट या रिस्ट वॉच वितरित किये जाने का प्रस्ताव रखकर स्पष्ट किया था कि निर्माणी कर्मचारियों को उससे कम का गिफ्ट स्वीकार नहीं होगा। जबकि निर्माणी प्रशासन ने प्रस्ताव दिया था, कि वो अधिकतम 150 रुपए तक मूल्य का ही गिफ्ट दे सकता है । इतने कम मूल्य के गिफ्ट का कामगार यूनियन द्वारा सख्त विरोध किया गया था। यूनियन ने जारी विज्ञप्ति में आरोप लगाया निर्माणी बचाव संघर्ष समिति की वर्क्स कमेटी ने समझौता वादी नीति को अपनाते हुए प्रशासन के सामने घुटने टेकने का काम किया है। कामगार यूनियन ने निर्माणी बचाव संयुक्त संघर्ष समिति सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक एंव लेबर यूनियन की वर्क्स कमेटी के क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए चुनोती दी है कि वर्क्स कमेटी त्याग पत्र दे देती है तो यूनियन निर्माणी प्रशासन से समस्त कर्मचारियों को ट्रेक सूट या रिस्ट वॉच वितरित करने का कार्य करेगी। इस संबंध की मांग राकेश शर्मा, रुपेश पाठक, राजेन्द्र चराडिया, प्रेम लाल सेन, लाल बहादुर राय, संजय प्रधान, के के शार्मा, दीपक सैनी, विजय भावे, विक्रम सिंह, राकेश पासवान आदि ने की है।

निगमायुक्त ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण

निगमायुक्त ने डोर टू डोर गाड़ियों की जीपीएस सिस्टम की जानकारी भी ली

जबलपुर (एजेंसी)। निगमायुक्त संदीप जी आर ने आज दमोहनाका स्थित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया और अधिकारियों की ऑन लाईन अटेण्डेंस चेक करने के साथ.साथ कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनिटरिंग सिस्टम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए तैयार वीटी एमएस प्रणाली का क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझा और स्वयं चेक कर वाहनों के संबंध में दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। निगमायुक्त संदीप जी आर ने कमांड कन्ट्रोल सेन्टर के कार्यो में और भी सुधार लाये जाने के निर्देश देते हुए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों की प्रभावी रूप से निगरानी करने के भी निर्देश दिये। इसके उपरांत निगमायुक्त ने शहर के कई इलाकों का भी निरीक्षण किया और साफ सफ ाई की व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी भूपेन्द्र सिंह को निर्देशित किया कि शहर की सफाई व्यवस्था में कोई कोताही न हो इस बात का ख्याल रखें और उन्होंने इसके लिए अपने नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों को भी लक्ष्य देने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान बालेन्दू शुक्ला एवं अन्य उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के प्रशासक बी चन्द्रशेखर के निर्देशानुसार शहर में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए प्रतिदिन अभियान चलाये जा रहे हैं, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा जारी स्वच्छता से संबंधित निर्देशों के अनुसार उसी मापदण्ड के अनुसार स्वच्छता संबधी कार्य भी बड़े पैमाने पर कराये जा रहे हैं ताकि स्वच्छता प्रतियोगिता में शहर की रैंकिंग में सुधार आए।

स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आए युवा : कुलपति प्रो. मिश्र

जबलपुर (एजेंसी)। छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। इस कोरोना के समय आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए यह सीखने को मिला है। उक्त विचार कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र ने मंगलवार को हितकारिणी महिला कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। हितकारिणी महिला कॉलेज एवं कौशल विकास संस्थान रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आत्मनिर्भर जबलपुर के अंतर्गत दो दिवसीय स्वरोजगार प्रदर्शनी का उद्घाटन कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आरडीयू कौशल विकास विभाग निदेशक प्रो. सुरेंद्र सिंह, कार्यक्रम अध्यक्षता शासी निकाय के अध्यक्ष एड. कमल कुमार जैन की मौजूदगी में दो दिवसीय स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं द्वारा निर्मित उत्पादों से संबंधित प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। तकनीकी सहयोग इनरव्हील क्लब जबलपुर साउथ के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। हितकारिणी महिला कॉलेज प्राचार्य डॉ. निलेश पांडे ने समस्त अतिथियों को प्रदर्शनी का अवलोकन कराया। इस अवसर पर के के गुरु, डॉ. सुनंदा जैन, डॉ.सुनीता श्रीवास्तव, डॉ. अजय मिश्रा, इंजी. महावीर, डॉ. रीतेश चौरसिया सहित समस्त अध्यापक कर्मचारी उपस्थित रहे। संचालन संजय सिंह राठौड़ ने किया।

पोलियो टीकाकरण अभियान के दिन में बदलाव से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, 15 करोड़ से अधिक बच्चों को वैक्सीन की डोज

नई दिल्ली । सरकार ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआइडी) के दिन में बदलाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और इसे दो सप्ताह के भीतर संचालित किया गया तथा 15.8 करोड़ से अधिक बच्चों को खुराकें दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्रव्यापी एनआइडी चलाता है जिसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के नाम से जाना जाता है।

संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले समारोहों (अमृत महोत्सव) के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट में कोई विशिष्ट धनराशि नहीं आवंटित की है। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले समारोहों की योजना तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। इस समिति की अब तक दो बैठकें 25 नवंबर, 2020 और 26 फरवरी, 2021 को हुई हैं। उन्होंने कहा कि समारोह 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू हो जाएंगे।

देश में पिछले 18 महीनों में साइबर अपराध की 3,17,439 घटनाएं हुई और 5,771 प्राथमिकी आनलाइन माध्यम से दर्ज की गई हैं। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक साइबर अपराध के मामलों में सबसे आगे रहे। रेड्डी ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत 30 अगस्त, 2019 को की गई थी ताकि लोगों को सभी तरह के साइबर अपराधों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत के बाद साइबर अपराध की 3,17,439 घटनाएं हुई। इन मामलों में 5,771 प्राथमिकियां भी दर्ज की गईं।

लाल किला में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किला की सुरक्षा पर्याप्त है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की सुरक्षा उसे हासिल है। सदन में 26 जनवरी को कृषि कानूनों का विरोध करने वालों के लाल किला में घुसने की घटना को लेकर सवाल उठाया गया था।

स्वरोजगार के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा शासन : मुख्यमंत्री

जबलपुर (एजेंसी)।

उच्च शिक्षा विभाग का यह नया कीर्तिमान है। कि प्रदेश में पहली बार लगभग 18000 विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत जो विद्यार्थी स्वरोजगार करना चाहते है, उन्हें 30 दिनों के भीतर सभी प्रकार की सुविधा शासन उपलब्ध करायए गा। उपरोक्त जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों से रूबरू होकर प्रदान की। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग, मप्र शासन भोपाल द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियो हेतु अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य अतिथ्य में 9 मार्च को भोपाल से ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ।

ऑनलाईन कार्यक्रम में उचच शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्यार्थियों की लगन एवं एकाग्रता की प्रशंसा की साथ ही डॉ.उमेष सिंह, निदेशक स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजनाए गोविंद राय, डॉ.भारद्वाज को कार्यक्रम हेतु बधाई दी। आयोजन के संबंध में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उशिवि डॉ. लीला भलावी ने बताया कि उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जबलपुर संभाग के लगभग 3380 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। संभागीय समन्वयक प्रो.अरुण शुक्ल ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित किया गया। प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया। उक्त प्रशिक्षण में जबलपुर संभाग के सभी जिलो नोडल अधिकारी, शासकीय कॉलेजों के मेंटर एवं विद्यार्थियों के सहयोग से सफल हुआ। भविष्य मे शासन द्वारा शेष विद्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण की योजना शासन द्वारा शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। इस अवसर पर वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्राचार्य डॉ. आभा पाण्डेय, डॉ.अखिलेश अयाची, जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजलक्ष्मी त्रिपाठी, डॉ.प्रतिभा कुमार के साथ कॉलेज के मेंटर एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद, भावनगर तथा वडोदरा के महापौर के नाम पर लगी मुहर; शेष पदों पर मंथन जारी

अहमदाबाद । गुजरात भाजपा संसदीय बोर्ड ने अहमदाबाद, भावनगर तथा वडोदरा के महापौर के नामों पर मुहर लगा दी है। किरीट परमार अहमदाबाद के महापौर होंगे, कीर्ति बेन दाणीधारिया भावनगर की महापौर होंगी जबकि केयूर भाई रोकडिया वडोदरा के महापौर होंगे। गुजरात की 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव 21 फरवरी को हुए थे, 23 फरवरी को 6 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई।

पंचायत में पालिका चुनाव के चलते अभी तक महापौर के नामों की घोषणा नहीं हो सकी थी लेकिन बीते दो दिनों से प्रदेश भाजपा संसदीय बोर्ड तथा पार्टी के कोर कमेटी के सदस्यों ने एक के बाद एक बैठक कर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति तथा पक्ष के नेता के नामों पर अंतिम मुहर लगाई। अहमदाबाद महानगरपालिका का महापौर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था इसलिए किरीट परमार को महापौर के रूप में चुना गया। गीता बेन पटेल को अहमदाबाद की उपमहापौर चुना गया है जबकि हितेश बारोट स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं भास्कर भट्ट को महानगर पालिका में पक्ष का नेता बनाया गया है।

भावनगर महापौर के लिए कीर्ति बेन दानीधारिया को चुना गया है जबकि उप महापौर के लिए कुणाल शाह के नाम पर सहमति बनी। वडोदरा के महापौर के लिए केयूर भाई रोकडिया तथा उप महापौर के लिए नंदा में जोशी के नाम की घोषणा की गई है। गांधीनगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय श्रीकमलम् भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संसदीय समिति की बैठक पिछले दो दिनों से चल रही थी जिसमें सभी छह महानगर पालिकाओं के लिए महापौर उपमहापौर तथा जिला पंचायतों व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष आदि के नामों पर चर्चा की गई। भाजपा के मीडिया प्रभारी यज्ञेश दवे ने बताया कि सूरत, राजकोट तथा जामनगर के महापौर, उपमहापौर व अन्य पदों के लिए भी मंथन जारी है जल्द ही उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में हाल ही संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका तथा जिला पंचायतों में भारी बहुमत मिला तथा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस एक भी शहर अथवा महानगर में जीत हासिल नहीं कर पाई। इस चुनाव में सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बन कर उभरी जबकि गोधरा में मोडासा नगरपालिका में एआईएमआईएम ने भी खाता खोलने के साथ प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका हासिल कर ली है। ए आई एम आई एम के अहमदाबाद महानगर पालिका में भी 7 पार्षद जीतकर आए हैं।

राजस्थान के धौलपुर में दूसरा विवाह करने की जिद में बिजली के खंभे पर चढ़ा बुजुर्ग

जयपुर । राजस्थान के धौलपुर में दूसरा विवाह करने की जिद में 5 बच्चों का 60 वर्षीय पिता बिजली के खंभे पर चढ़ गया। परिजन इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उसने हाईटेंशन लाइन पकड़ ली, गनीमत यह रही कि उस समय विधुत निगम ने बिजली की आपूर्ति बंद कर रखी थी। बुजुर्ग को बड़ी मुश्किल से खंभे से उतारा गया।

जानकारी के अनुसार बुजुर्ग रामजस की पत्नी का निधन करीब चार साल पहले हो गया था। अब वह दूसरा विवाह करना चाहता था, लेकिन परिजन इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। वह काफी समय से परिजनों पर दबाव बना रहा था, लेकिन नहीं माने तो दो दिन पहले बिजली के खंभे पर छड़कर अपनी बात मनवानी चाही। जैसे ही वह बिजली के खंभे पर चढ़ रहा था, आसपास के लोगों ने देख लिया और बिजली की सप्लाई बंद करा दी। इस कारण उसे करंट का झटका नहीं लगा। जिस खंभे पर वह चढ़ा वहां से 11 केवी की बिजली की लाइन गुजर रही थी। खंभे पर चढ़े बुजुर्ग ने नीचे खड़े परिजनों से कहा कि दूसरा विवाह करने की अनुमति देते हो या मैं लाइन पकड़ कर आत्महत्या कर लूं।

परिजन फिर भी तैयार नहीं हुए तो उसने लाइन पकड़ ली। हालांकि उसे करंट नहीं लगा। बाद में मौके पर मौजूद एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर खंभे पर चढ़ा और बुजुर्ग को नीचे उतारा। इसी बीच पुलिस और बिजली कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग को हिरासत में लेकर समझाने के बाद घर भेज दिया गया। बुजुर्ग दादा और नाना बन चुका, लेकिन फिर भी वह दूसरा विवाह करना चाहता था। दो दिन पुराने इस घटनाक्रम का वीडियो मंगलवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है।

अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के अंदर एक नगरपालिका कर्मी कीटनाशक का छिड़काव करते हुए।

खासी मांग है देश के साथ-साथ विदेशों में भी

मेडीकल लैब टैक्नीशियन की

मेडीकल लैब टैक्नीशियन, डाक्टरों के निर्देश पर काम करते हैं। उपकरणों के रख-रखाव और कई तरह के काम इनके जिम्मे होता है। लैबोरेटरी में नमूनों की जांच और विश्लेषण में काम आने वाला घोल भी लैब टैक्नीशियन ही बनाते हैं। इन्हें मेडीकल साइंस के साथ-साथ लैब सुरक्षा नियमों और जरूरतों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। लैब टैक्नीशियन नमूनों की जांच का काम करते हैं, लेकिन वे इसके परिणामों के विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित नहीं होते।

नमूनों के परिणामों का विश्लेषण पैथोलॉजिस्ट या लैब टैक्नोलॉजिस्ट ही कर सकता है। जांच के दौरान एम.एल.टी. कुछ सैम्पलों को आगे की जांच या फिर जरूरत के अनुसार उन्हें सुरक्षित भी रख लेता है। एम.एल.टी. का काम बहुत ही जिम्मेदारी और चुनौती भरा होता है। इसमें धैर्य और निपुणता की बड़ी आवश्यकता होती है। जमा किए गए डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की भी जिम्मेदारी उसकी होती है।

मेडीकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट में सर्टीफिकेट डिप्लोमा, डिग्री एवं मास्टर्स के दौरान बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकैमिस्ट्री एंड ब्लड बैंकिंग, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, एनवायरनमैंट एंड बायोमैडीकल वेस्ट मैनेजमैंट, मैडीकल लैबोरेटरी टैक्नोलॉजी एवं अस्पताल प्रशिक्षण दिया जाता है।

सर्टीफिकेट इन मैडीकल लैब टैक्नोलॉजी (सी.एम.एल.टी.) छह महीने का कोर्स है जिसके लिए योग्यता है 10वीं पास। वहीं डिप्लोमा इन मैडीकल लैब

टैक्नोलॉजी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इस कोर्स की अवधि है एक वर्ष। 12वीं प्रमुख विषय के रूप में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी (पी.सी.बी.) तथा फिजिक्स, कैमिस्ट्री या मैथ्स (पी.सी.एम.) के साथ पास होना अनिवार्य है।

बी.एससी. इन एम.एल.टी. के लिए 12वीं विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। जिसकी अवधि है 3 वर्ष। एम.एस.सी. इन मैडीकल लैबोरेटरी टैक्नोलॉजिस्ट (एम.एल.टी.) प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए अभ्यर्थी के पास पहले हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, इसके बाद 2 साल का एसोसिएट प्रोग्राम करना होता है। यह प्रोग्राम कम्युनिटी कालेज, टैक्नीकल, स्कूल, वोकेशनल स्कूल या विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है।

मैडीकल लैबोरेटरी तकनीशियनों को काम में निपुणता और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है।

छात्र इस तरह क प्रशिक्षण लैबोरेटरी कार्यों के दौरान ही साथ ही साथ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर प्रांतों में मैडीकल लैबोरेटरी तकनीशियनों के लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ राज्यों में इन तकनीशियनों के पास काम करने के लिए प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

प्रमाण पत्र वाले तकनीशियनों के लिए इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं होती हैं। आप किसी भी मैडीकल लैबोरेटरी हॉस्पिटल, पैथोलॉजिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। ब्लड बैंक में इनकी खासी मांग रहती है। आप बतौर रिसर्चर व कंसल्टैंट के अलावा खुद का क्लीनिक खोल सकते हैं।

सामान्य तौर पर एक एम.एल.टी. का वेतन 10 हजार से शुरू होता है जबकि पैथोलॉजिस्ट को तीस हजार रुपए से चालीस हजार रुपए तक सैलरी मिल जाती है। साथ ही योग्यता और तजुर्बे के आधार पर उनके वेतन में इजाफा होता चला जाता है। देश के साथ-साथ विदेशों में भी इनकी खासी मांग है।

आधे से ज्यादा लोग अपनी जॉब से रहते हैं

नाखुश!

क्या आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा लोग अपनी नौकरी से नाखुश रहते हैं और आधे से ज्यादा लोग इस बात को महसूस करते हैं कि वह जिस जॉब को कर रहे हैं, उसमें उनका कोई भविष्य नहीं है या उन्होंने अपनी जिंदगी में गलत करियर चुन लिया।

यह बात ब्रिटेन स्टडी में सामने आई है। स्टडी में कहा गया है कि ब्रिटेन में काम करने वाले लोग अपनी जॉब से परेशान हैं और वह मानते हैं कि वह अपने भविष्य को सही जगह नहीं ले गए। इसके साथ ही एक चौथाई लोग अपने आपको गरीब कर्मचारी मानते हैं। वह लोग ऐसा इसिलए समझते हैं, क्योंकि वह अपनी जॉब से खुश नहीं होते।

स्टडी के मुताबिक 7 में से 1 कर्मचारी ऐसा भी होता है, जो अपनी जॉब से परेशान होकर उसकी आदर नहीं करते और वह जॉब पर ध्यान नहीं देता। इसके साथ-साथ 49 फीसदी ब्रिटेन के कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो जॉब करने के साथ साथ किसी और फिल्ड में भी अपना कैरियर तलाश करते हैं।

प्रतिद्वंद्वी को अपना अच्छा दोस्त बनाएं

जब दोस्त ईष्या करने लगे

कई बार ऑफिस में प्रमोशन मिलने से आपकी बैस्ट फ्रैंड को भी आपसे ईर्ष्या हो जाती है। ऐसे में अपनी ही दोस्त के बिहेवियर में जलन का भाव देख कर किसी को भी टैंशन होना लाजिमी है, उसे बताएं कि बहुत सी चीजें वक्त के साथ ही संभव हो पाती हैं, कल उसे भी तो प्रमोशन मिल सकता है, बस मेहनत करते रहो। इस प्रकार दो दोस्तों के दिलों में पडने वाली दीवार को समय रहते मिटाया जा सकता है।

शिकायत करने वालों से बचें

ऐसे दोस्तों की भी कमी नहीं जिसे हमेशा आपसे कोई न कोई शिकायत रहती हो। हर बार कमी गिनाने वाले लोग पॉजीटिव सोच वाले नहीं हो सकते। अतः जरूरी है कि उसकी अधिकांश शिकायतों को उसकी आदत जान कर नजरअंदाज करना आरंभ करें। जब भी वह आपसे शिकायत करने लगे तो बात का टॉपिक ही बदल दें, यदि फिर भी वह न समझे, तो उसे साफ.-साफ कह दें कि हर समय अपनी कमी सुनना अपको पसंद नहीं और वह भी अपने नैगेटिव थॉट्स छोड़ कर पॉजीटिव बातों की तरफ ध्यान दे।

हमेशा सलाह देने वालों से बचें

कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने फ्रैंड्स को परेशान देख कर बिना उसकी परेशानी का सबब जाने ही उसे सलाह देने बैठ जाएंगे, बिना यह जाने कि उसे इसकी जरूरत है भी या नहीं। ऐसे दोस्तों को लगता है कि आप में किसी प्रकार का फैसला लेने की क्षमता नहीं है और आपकी भलाई हमेशा उन्हें ऐसा करने को प्रेरित करती रहती है।

अब भले ही आपको यह सब बुरा लगे, पर इतनी सी बात पर दोस्ती कोई नहीं तोड़ता। अब की बार जब वह आपको बिन मांगे सलाह देने लगे तो बड़े प्यार से उसे यह समझाएं कि आप उसकी सलाह एवं राय का आदर करती हैं पर आप भी दूसरों की तरह अपनी ही गलतियों से सीखना चाहती हैं। यदि आपको उसकी सलाह की आवश्यकता होगी तो आप स्वयं उससे सलाह मांग लेंगी, तब तक उन्हें खुद ही इसका हल ढूंढने दिया जाए।

खुद करें पहल

दोस्ती एक ऐसा फेवीकोल है जो बिखरते रिश्तों को मजबूती से जोडने का काम करता है। यदि आप किसी दूसरे से बेहतर बनना चाहती हैं, तो उसकी दोस्त बन जाएं, फिर आपको उससे प्रतिस्पर्धा करने में तनाव भी नहीं होगा और आपको एक नया दोस्त भी मिल जाएगा, जिससे आप प्रतिदिन कुछ नया सीखेंगी। नए रिश्ते बनाने में पहल किसी को तो करनी ही होती है, तो क्यों न आप ही शुरूआत करें क्योंकि प्रतिद्वंद्वी को ही अपना अच्छा दोस्त बनाने से बेहतर और क्या हो सकता है।

बीती बातों को भुलाना बेहतर

कभी किसी दोस्त के लिए गुस्से में अपशब्द निकल गए हों तो उसे भुला कर उससे माफी मांग लें, क्योंकि बीती बातों को दोहराने का कोई लाभ नहीं। माफी मांग लेने से आप एक अच्छे दोस्त को खोने से बच जाएंगी और साथ ही उसकी नजरों में आपका स्थान और ऊंचा हो जाएगा।

अनुवादक

कॅरियर का बेहतरीन विकल्प

आज दुनिया भर के कई देशों में डिस्कवरी सबसे लोकप्रिय चैनल है। यह चैनल दुनिया के कई देशों में उनकी भाषा में प्रसारण करता है। ऐसा संभव होता है अनुवाद के कारण। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसने ग्लोबल दुनिया को एक-दूसरे से जुडने में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया की कई भाषाओं में अच्छे अनुवादकों की आज भारी मांग है। अच्छे अनुवादकों को अच्छा काम और अच्छा पैसा मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। अच्छे अनुवादक की योग्यता- यह ध्यान रखने की बात है कि अनुवाद मूल लेखन से भी मुश्किल है। सबसे पहले आपको अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा की जानकारी हो। इसके लिए महज फर्राटे से स्पैनिश और फ्रेंच बोलने से काम नहीं चल जाता। अनुवादक का मकसद एक से दूसरे भाषा क्षेत्र में जाना होता है। इसलिए इसके लिए धैर्य, स्थिरता और समय की जरूरत होती है। अनुवाद शुरू करने से लेकर खत्म करने तक में अनुवादक को कई तरह के प्रयोग करने होते हैं। शब्दों के विकल्पों में से सटीक शब्द चुनना होता है। मूल लेखन और टारगेट रीडर के बीच की दूरी खत्म करनी होती है। यह दूरी जितनी ज्यादा कम हो जाए, अनुवाद उतना सफल होता है। अवसर- शिक्षा और मीडिया से जुड़े लोगों के बीच अनुवाद के काम की बहुत मांग है। विभिन्न दूतावासों में भी अच्छे अनुवादकों की दरकार होती है। फिल्मों और धारावाहिकों में डबिंग के लिए भी अनुवादक की जरूरत होती है। एक प्रोफेशनल अनुवादक के लिए रोजगार के कई अवसर हैं। आज देश में लगभग पांच करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें तीन भाषाओं का ज्ञान है। आने वाले समय में यह संख्या बढ़ेगी जिसके कारण रोजगार की संख्या बढ़ेगी। जिन लोगों को दो या तीन भाषाओं की अच्छी जानकारी होती है, वे अनुवादक के रूप में अच्छा करिअर बना सकते हैं। अनुवाद का मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अनुवाद दरअसल एक सेतु है, जो दो भाषाओं, दो संस्कृतियों और दो सभ्यताओं को आपस में जोड़ता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में अनुवादकों की माँग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अनुवाद करने वालों के लिए प्रकाशन गृह में हमेशा स्थान होता है। इसके अलावा फिल्मी दुनिया में भी विदेशी फिल्मों के सबटाइटल' बनाने और

> भाषा संप्रेषण का माध्यम है लेकिन यदि भाषा पर अधिकार हो तो करिअर बनाने की डगर बहुत आसान हो जाती है। वैसे तो आप किसी भी क्षेत्र में अपना करिअर बनाएँ, दो या दो से अधिक भाषाओं पर अच्छी पकड़ आपको हर क्षेत्र में खास तवज्जो दिलाएगी। दो भाषाओं पर अच्छा अधिकार अपने आप में एक विशेषता है।

किसी अन्य भाषा में फिल्म की डबिंग करने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है। अखबार और पत्रिकाओं में भी अनुवाद का बहुत काम होता है, इसलिए प्रिंट मीडिया में भी अनुवादकों के लिए अवसर मौजूद होते हैं। निजी क्षेत्र के अलावा शासकीय क्षेत्र में भी अनुवादकों के लिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होते हैं। शासकीय दूतावासों में अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूतावास में काम करने वाले अनुवादकों को विदेश जाने के अवसर एवं प्रतिष्ठापूर्ण ओहदा मिलता है। कई लोग अनुवाद को केवल हिंदी और अंग्रेजी के साथ जोड़कर ही देखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अनुवाद के संदर्भ में हिंदी और अंग्रेजी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन अन्य भाषाओं में भी अनुवाद के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। यदि हम अपने देश के बारे में बात करें तो हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, कन्नड, तमिल जैसी भाषाओं में भी अनुवादकों के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। यदि अनुवादक के रूप में नौकरी न करना चाहें तो फ्रीलांस अनुवादक के रूप में काम किया जा सकता है। फ्रीलांस अनुवादकों के लिए भी अवसरों की कमी नहीं है। फ्रीलांस अनुवादकों के लिए इंटरनेट बहुत बड़ा अवसरदाता है। कई वेबसाइट अनुवादकों को अवसर मुहैया करवा रही है। इन साइटों पर अनुवादक अपना पंजीयन करवाते हैं।

मेलबोर्न में मार्श कप में बल्लेबाजी करते हुए जोर्डन सिल्क।

हर दिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदर्शन करने पर ही टीम में रह सकते हैं : झूलन

फिटनेस का स्तर बनाये रखना और मैदान पर शानदार प्रदर्शन करना जरूरी है

लखनऊ, (एजेंसी)। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का मानना है कि लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ फिटनेस का ऊंचा स्तर भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बने रहने के लिये जरूरी है। अड़तीस वर्ष की गोस्वामी महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 231 विकेट ले चुकी है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 42 रन देकर चार विकेट लेकर भारत की नौ विकेट से जीत में सूत्रधार की भूमिका निभाई। उन्होंने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, भारत के लिये खेलना मेरे लिये सबसे बड़ी प्रेरणा है।

इससे इतर किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप हर दिन अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ नहीं रख सकते तो टीम में बने रहने के हकदार नहीं है। फिटनेस का स्तर बनाये रखना और मैदान पर शानदार प्रदर्शन करना जरूरी है। यह आसान नहीं है। बंगाल की इस तेज गेंदबाज ने 2018 में टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कहा, जब मैने टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया, तब सबसे अहम बात एक ही प्रारूप पर फोकस करने की थी। मेरे लिये फिटनेस का स्तर बनाये रखना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद मैने प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश की। लॉकडाउन के दौरान काफी मेहनत की। भारत के लिये खेलना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, जिम्मेदारी और काम है।

टी20 मैचों के लिए अंतिम ग्यारह खिलाड़ियों का चयन आसान नहीं होगा

मुम्बई, (एजेंसी)। भारतीय टीम के लिए शुक्रवार से अहमदाबाद में शुरू होने वाले पांच टी20 क्रिकेट मैचों के लिये अंतिम ग्यारह खिलाड़ियों का चयन आसान नहीं रहेगा। ऐसे में मुख्य कोच रवि शास्त्री, कप्तान विराट कोहली और गेंदबाजी कोच भरत अरूण को कई बातों का ध्यान रखना होगा। माना जा रहा है कि पहले तीन मैचों के लिये अंतिम ग्यारह का चयन होगा। इसका कारण है कि सभी मैच एक ही स्टेडियम में समान पिच पर होंगे। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का प्रदर्शन हाल के दिनों में शानदार रहा है। ऐसे में लोकेश राहुल को शायद ही विकेटकीपर के तौर पर टीम में जगह मिले। वहीं सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन और रोहित शर्मा कुछ समय पहले तक पहली पसंद रहेंगे पर अब धवन की दावेदारी कमजोर नजर आ रही है क्योंकि राहुल भी सलामी बल्लेबाज के लिए एक प्रतियोगी के तौर पर उभरे हैं।

कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर आते हैं जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर खेलेंगे। ऐसे में राहुल को चौथे स्थान के लिए श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव से स्पर्धा करनी होगी। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में भुवनेश्वर कुमार लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं और ऐसे में उनका मुकाबला दीपक चाहर और शारदुल ठाकुर से रहेगा। भुवनेश्वर हालांकि अपने अनुभव और डेथ ओवरों में बेहतर गेंदबाजी के कारण चाहर से आगे रहेंगे। उन्होंने कुछ मुश्ताक अली मैचों के अलावा ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है। युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल तीन स्पिनर हैं जिन्हें मोटेरा की पिच पर अंतिम ग्यार में जगह मिल सकती है। वहीं टी नटराजन अपनी यॉर्कर में विविधता की वजह से नवदीप सैनी पर भारी रहेंगे।

सूर्यकुमार से सीखें युवा खिलाड़ी : लक्ष्मण

मुंबई, (एजेंसी)। स्टायलिश बल्लेबाज के तौर पर लोकप्रिय वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव से सीखना चाहिये। लक्ष्मण ने लंबे इंतजार के बाद हाल ही में भारतीय टीम में शामिल सूर्यकुमार को युवाओं के लिए एक आदर्श खिलाड़ी बताया। सूर्यकुमार को शुक्रवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। सूर्यकुमार की तारीफ करते हुए लक्ष्मण ने कहा, 31 साल का ये खिलाड़ी एक आदर्श उदाहरण है कि यदि कोई धैर्यवान रहता है तो उसे सफलता जरुर मिलती है। लक्ष्मण ने कहा, वह इसके अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि वह युवाओं के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं, खासकर भारत में क्योंकि हम लोब बहुत जल्दी ही धैर्य खो देते हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छे रन बनाने वाले सभी खिलाड़ी भारतीय टीम में आने की उम्मीद करते हैं हालांकि यह कठिन होता है। इसका कारण गुणवत्ता, प्रतिभा और बेहद ज्यादा प्रतियोगिता का होना है, पर यहां सूर्यकुमार ने लगातार प्रयास जारी रखे जिससे अंत में उन्हें टीम में जगह मिल गयी। लक्ष्मण ने कहा, वह पहले दर्जे के क्रिकेट में वापस जाता है, मुंबई के लिए स्कोर बनाता है, जब भी उसे मुंबई इंडियंस के लिए मौका मिलता है, तो वह एक सकारात्मक रन बनाने वाला खिलाड़ी बनकर उभरता है। उन्होंने कहा, वह कठिन हालातों में खेलते हैं और मैच जीतते हैं और यही आप एक खिलाड़ी से उम्मीद करते हैं। अंततः एक कहावत है, जिसे मेरे कोच ने मुझे जल्दी सिखाया था, यदि चयनकर्ता दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो दरवाजा खोलो।

ऋषभ पंत का शतक लगाना नासिर हुसैन को चुभा, इंग्लैंड को लताड़ा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतने के बावजूद सीरीज 1-3 से हारने वाली टीम इंग्लैंड पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व कप्तान ही उठा रहे हैं। माइकल वॉन के बाद अब पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी पर सवाल खड़ा किया है।

नासिर हुसैन ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपने खिलाड़ियों को गलत समय और सीरीज में रोटेट किया है। नासिर हुसैन ने लिखा कि वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम की रोटेशन पॉलिसी की जरूरत को समझते हैं, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया है वो बिलकुल गलत है। एक ओर जहां भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत शतक लगा रहे थे वहीं इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर होटल रूम में बैठे हुए थे।

नासिर हुसैन ने लिखा, इंग्लैंड की सबसे बड़ी समस्या चयन, आराम और रोटेशन नहीं है। उसकी समस्या है एक साल में 17 टेस्ट मैच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बड़े दौरे, टी20 वर्ल्ड कप, 2 आईपीएल मैं ईसीबी से सहमति रखता हूं कि वो अपने खिलाड़ियों का ध्यान रख रही है और उन्हें रोटेट कर रही है। लेकिन यहां असल मुद्दा ये है कि उन खिलाड़ियों को रोटेट कैसे किया जा रहा है। भारत के खिलाफ सीरीज एक बड़ा मुकाबला है और आप अपने खिलाड़ियों को गलत समय पर रोटेट कर रहे हो। नासिर हुसैन ने लिखा, अहमदाबाद में ऋषभ पंत चारों ओर गेंद को मार रहे थे और जोस बटलर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो उसी शहर के होटल में आराम कर रहे थे। वजह थी आगे आने वाली वनडे और टी20 सीरीज। ये मुझे बिलकुल भी सही नहीं लगा। इग्लैंड क्रिकेट टीम ने टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीतने के बाद जोस बटलर को आखिरी तीन टेस्ट मैचों में आराम दिया और पांच विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन को अगले मैच में आराम दिया। यही वजह है कि टीम इंडिया सीरीज में वापसी कर सकी और अंत के तीनों मैच जीतकर उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली।

ऑकलैंड में इटली की रुना लोसा और टीम न्यूजीलैंड अमेरिका कप में भाग लेते हुए।

तोक्यो ओलंपिक में बढ़ी झारखंड से पदक की उम्मीद

रांची, (एजेंसी)। तोक्यो ओलंपिक में गोल्ड को लेकर देश की नजरें झारखंड की ओर टिकती नजर आ रही है। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं दो और महिला तीरंदाज ने भी ओलंपिक के टिकट के लिए प्रबल दावेदारी में हैं। सवाल यह है कि व्यक्तिगत प्रदर्शन के बूते खुद को साबित कर चुकी तीरंदाज बेटियों के लिए राज्य सरकार की प्रशिक्षण व्यवस्था कितनी मुकम्मल है। वक्त आ गया है तोक्यो ओलंपिक के गोल्ड पर निशाना साधने और उम्मीद भरी नजरों से झारखंड की ओर देखने का। तीरंदाज दीपिका ने एक बार फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हुए तोक्यो में गोल्ड पर निशाना साधने की कोशिश करेंगी। वहीं कोमोलिका बारी और अंकिता भकत भी तोक्यो ओलंपिक के लिए प्रबल दावेदार हैं। सवाल यह भी है कि क्या झारखंड सरकार ओलंपिक को लेकर अपने तीरंदाजों को विदेशी आवोहवा में ढलने के लिए क्या कुछ समय पहले तोक्यो भेज सकती है। क्या इसको लेकर भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ कोई बातचीत या पहल की गयी है।

हम इन तमाम सवालों को लेकर राज्य सरकार की सबसे उच्च गुणवत्ता और प्रशिक्षण वाले एकलव्य तीरंदाजी केंद्र पहुंचे, जहां कोच ने भी साफ कहा कि तोक्यो के वातावरण और आवोहवा को समझने के लिए थोड़ा पहले तीरंदाजों को वहां भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीरंदाजों को लेकर राज्य सरकार की प्रशिक्षण व्यवस्था हालांकि बेहतर है लेकिन ओलंपिक और वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिता के लिए काफी सुधार की जरूरत है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से राज्यभर में तीरंदाजी प्रशिक्षण को लेकर पांच आवासीय केंद्र हैं। जिसमें रांची के सिल्ली, दुमका, सरायकेला खरसांवा, चाईबासा का कुमारडुबी और बोकारो का चंदनकियारी में प्रशिक्षण केंद्र है। जो बच्चे इन आवासीय विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन कर खुद को राज्यस्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर साबित करते हैं। उनके लिए रांची के होटवार और दुमका के दुधानी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र हैं। इसके अलावा रांची के मेगास्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में राज्य सरकार और सीसीएल के सहयोग से चेएसएसपीएस के माध्यम से भी छोटे बच्चों को तीरंदाजी के गुर सिखाये जा रहे हैं। यहां प्रशिक्षण ले रहे कई खिलाड़ी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर साबित कर पदक जीत चुके हैं। मेगास्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स और सेंटर फॉर एक्सीलेंस एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र का मकसद ही ओलंपिक जैसे बड़े टूनार्मेंट को लेकर तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर तैयार करना है। ऐसे में खिलाड़ियों को विदेशी माहौल में ढलने के लिए झारखंड तीरंदाजी संघ की ओर क्या पहल की जाती है। इसपर सबकी नजर है।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कुर्सी पर मारा बल्ला

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्कस हैरिस इन दिनों अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और इसी वजह से वो बेहद निराश भी हैं। उनकी निराशा शैफील्ड शील्ड में तस्मानिया के खिलाफ एक मुकाबले में देखी गई, जब उन्होंने आउट होने के बाद अपना बैट मैदान के बाहर रखी कुर्सी पर दे मारा। यही नहीं उन्होंने अपने बैट को भी मैदान पर बुरी तरह पटका जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मार्कस हैरिस को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया है। विक्टोरिया के इस बल्लेबाज ने 5 मार्च को हुए मुकाबले में अपना बैट कुर्सी पर मारा। दरअसल मार्कस हैरिस अंपायर के फैसले से निराश थे। अंपायर ने उन्हें कैच आउट दिया और हैरिस का दावा था कि गेंद उनकी कोहनी पर लगी है। हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। हैरिस को लेवल 1 के तहत दोषी पाया गया जिसके तहत उनपर एक मैच का बैन और 50 फीसदी मैच फीस का जुमार्ना लगा है। मार्कस हैरिस 18 महीने में दूसरी बार ऐसी हरकत करते हुए पाए गए हैं। 2019 में उन्होंने तस्मानिया के खिलाफ ही बोल्ड होने के बाद अपना बैट स्टंप पर दे मारा था। जिसके बाद उनकी 25 फीसदी मैच फीस काट ली गई थी। विक्टोरिया को अब अपना अगला मैच क्वींसलैंड के खिलाफ 15 मार्च को खेलना है जिसकी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा मार्कस हैरिस नहीं होंगे। बाएं हाथ के मार्कस हैरिस पिछले कुछ समय से बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। हैरिस ने लगातार 13 पारियों से अर्धशतक नहीं लगाया है। हालांकि वो 11 पारियों में दोहरे अंकों तक जरूर पहुंचे हैं। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने मौका दिया था लेकिन वो 5 और 38 रनों की पारी खेल आउट हो गए।

टीम इंडिया में शामिल होंगे राहुल चाहर!

नई दिल्ली, (संवाददाता)। 12 मार्च से भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज करना है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये है कि टीम में एक और खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल चाहर को भारतीय टी20 टीम में मौका मिल सकता है। राहुल चाहर को सेलेक्टर्स ने इससे पहले नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती और राहुल तेवतिया की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए ध्यान राहुल चाहर पर गया है। राहुल चाहर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया के साथ स्टैंडबाई खिलाड़ी के तौर पर जुड़े हुए थे। 8 मार्च को उन्होंने अहमदाबाद में ही टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस भी की लेकिन उन्हें टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया। हालांकि अब रिपोर्ट के मुताबिक राहुल चाहर टी20 टीम में आ सकते हैं।

भारत के लिए एक टी20 मैच खेल चुके राहुल चाहर ने आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। राहुल चाहर ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू भी किया, लेकिन इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिल सका। इंग्लैंड सीरीज में भी उनपर वरुण चक्रवर्ती और राहुल तेवतिया को तरजीह दी गई लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने बैंगलोर में हुए फिटनेस टेस्ट में ये दोनों खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे। बता दें राहुल तेवतिया भी इस वक्त टीम इंडिया के साथ अहमदाबाद में हैं लेकिन उनके दूसरे फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट अबतक सामने नहीं आई है। वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस करते नहीं दिखे हैं और ऐसी खबरें हैं कि उन्हें बैंगलोर में स्थित एनसीए में भेजा गया है।

इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया- विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, इशान किशन, युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर।

डोरमंट में सेवेला के गोलकीपर यूसुफ अल नेसरी चैम्पयंसलीग फुटबॉल में गोल करते हुए।

इंग्लैंड की टीम में वापस लौटे सैम करन

अहमदाबाद, (एजेंसी)। इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी सैम करन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि आईपीएल ने उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आईपीएल खेलना बहुत शानदार अनुभव रहा। इंग्लैंड की टीम में वापस लौटे करन ने कहा, पिछले साल यूएई में आईपीएल के दौरान मैंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं और विभिन्न तरीकों से चुनौतियों का सामना किया, जिसका मैंने खूब आनंद लिया। करन ने कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए लाभदायक रहा। आईपीएल शानदार टूनार्मेंट है, हमारे जैसे खिलाड़ी आईपीएल में खेलना पसंद करते हैं। यहां प्रशंसकों की बहुत भीड़ होती है। वाकई भारत क्रिकेट खेलने के लिए उम्दा स्थान है। आईपीएल सर्वश्रेष्ठ टी-20 टूनार्मेंट है और हम खुश हैं कि टी-20 विश्व कप भी भारत में हो रहा है। इससे हमारी अच्छी तैयारी होगी और हमें यहां की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा, काम के दबाव और कोरोना वायरस के कारण बायो बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) जैसी परेशानियों के बावजूद कहा कि अब भी उनका यही लक्ष्य है कि वह इंग्लैंड के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेलें। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैक्सीन के विस्तार से आगामी महीनों, खासतौर पर 2021-22 की एशेज श्रृंखला में पाबंदियों में कुछ छूट मिलेगी। करन ने इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी के बारे में कहा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह पॉलिसी लाभदायक लगी, लेकिन खिलाड़ियों के नजरिए से देखें तो बायो बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) काफी मुश्किल है। लंबे समय तक अकेले रहना पड़ता है। आराम के बाद जब वापस आया तो मैंने खुद को तरोताजा महसूस किया। बेशक भारत मजबूत टीम है, लेकिन इतनी ज्यादा क्रिकेट और बायो बबल के कारण इंग्लैंड का रुख स्पष्ट है कि वह अपने खिलाड़ियों को इसमें नहीं झोंकेगा। टीम प्रबंधन खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा रखना चाहता है।

तेज गेंदबाज जहीर खान पत्नी सहित पहुंचे मंदिर

रामगढ़, (एजेंसी)। पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान अपनी पत्नी सागरिका घाटगे के साथ मंदिर पहुंचे। झारखंड के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर में उन्होंने पूजा की। यहां दोनों ने मां के दरबार में मन्नत पूरी होने का पत्थर बांधा। जहीर खान के आने की खबर सुनते ही मंदिर परिसर के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। जहीर खान ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में करीब 15 मिनट तक छिन्नमस्ता देवी की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। जहीर खान के मंदिर में आने की सूचना मिलते ही वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जहीर खान और सागरिका घाटगे ने पूजा-अर्चना के बाद वहां मौजूद लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। जहीर खान और उनकी पत्नी सागरिका घाटगे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रांची आए हुए थे और इसी दौरान दोनों माता के दरबार में पहुंचे। जहीर खान ने कहा कि मां छिन्नमस्ता के बारे में सुना था। पत्नी की भी इच्छा थी कि एक बार मां छिन्नमस्ता के दर्शन करूं। यहां आकर बहुत अच्छा लगा। मनोकामना पूरी हुई तो फिर पूजा-अर्चना करने के लिए माता के दरबार में आएंगे। बता दें कि जहीर खान की पत्नी सागरिका घाटके कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हालांकि चक दे इंडिया से उन्हें पहचान मिली थी। इस फिल्म के लिए सागरिका को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला था। सागरिका रियल लाइफ में भी नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हैं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान ने भारत के लिए 92 टेस्ट मैच और 200 वनडे मैच खेले हैं। इसके अलावा जहीर खान ने 17 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 100 आईपीएल मैच खेले हैं। जहीर खान ने 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट और 200 वनडे मुकाबलों में 282 विकेट लिए हैं। जहीर खान ने 17 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 17 विकेट और 100 आईपीएल मुकाबलों में 102 विकेट झटके हैं।